● वर्ष-2
● अंक-151
रायपुर, शनिवार
11 फरवरी 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

इन दिनों

शशांक शर्मा

प्रदेश कांग्रेस संगठन में अंदरुनी कलह

कांग्रेस पार्टी के लिए संगठन के भीतर कलह होना या बड़े नेताओं की गुटबाजी के कारण विवाद होना कोई नई बात नहीं है। यही आश्चर्य का विषय है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के समय पार्टी एकजुट होकर कैसे लड़ी? 2003-2018 के बीच ज्यादातर चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के पीछे बड़े नेताओं की आपसी लड़ाई बहुत हद तक जिम्मेदार थी। पूर्व प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले सभी बड़े नेताओं को एकसूत्र में पिरो दिया था। लेकिन सरकार बनने के बाद जब मोहन मरकाम प्रदेश के अध्यक्ष बने उसके बाद सत्ता और संगठन के बीच मनमुटाव शुरु हो गया है। अभी कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी संगठन महामंत्री अमरजीत चावला को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस शिकायत के बाद जारी किया गया है जिसमें रायपुर में हो रहे कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय महाधिवेशन के आयोजन समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविन्द नेताम का नाम कर दिया गया था। पिछले दिनों भानुप्रतापपुर में हुए उपचुनाव के दौरान अरविन्द नेताम ने सर्वआदिवासी समाज के उम्मीदवार के पक्ष में बयान दिया था। स्वाभाविक है कि यह पार्टी विरोधी गतिविधि में आता है लेकिन दो माह बीत गए कांग्रेस पार्टी ने उनके पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इसका मतलब है कि अरविन्द नेताम अभी भी कांग्रेस पार्टी के नेता है। दूसरी ओर उनकी वरिष्ठता और केंद्र में मंत्री होने के व पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के निकट होने के कारण केंद्र के बड़े कांग्रेसी नेता उनका सम्मान करते है। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी हरियाणा से आई कुमारी शैलजा का भी अरविन्द नेताम के प्रति सम्मान है। संभव है कि यह आयोजन समिति में अरविन्द नेताम का नाम शामिल करने की पहल स्वयं प्रदेश प्रभारी ने की हो। इस आधार पर प्रभारी संगठन महामंत्री अमरजीत चावला ने जो सूची जारी कि उसमें अरविन्द नेताम का नाम आ गया। दूसरी ओर इस घटना के कारण संगठन के भीतर अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी महामंत्री के विरोधियों को उनके खिलाफ माहौल बनाने का एक अवसर मिल गया। केंद्रीय नेतृत्व से भी तो प्रदेश अध्यक्ष की भी शिकायत की गई थी। लेकिन नोटिस अरविन्द नेताम और अमरजीत चावला के नाम जारी किया गया है। यह घटना कांग्रेस पार्टी में सत्ता और संगठन के बीच वर्चस्व की लड़ाई की ओर इशारा करता है। चुनाव के पहले सत्ता और संगठन की यह लड़ाई पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी को एकजुट बनाए रखने के लिए समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी महासचिव की है।

काऊ हग डे का मजाक बनाना सही नहीं

पश्चिमी देशों में ऐसे आयोजन के सकारात्मक लाभ सामने आये हैं

गौतम मोरारका

यदि आप 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर लोगों से 14 फरवरी को ''काउ हग डे'' मनाने की अपील की है। पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत आने वाले बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, ''सभी गाय प्रेमी गौ माता की महत्ता को ध्यान में रखते हुए तथा जिंदगी को खुशनुमा और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण बनाने के लिए 14 फरवरी को काउ हग डे मना सकते हैं।'' नोटिस में कहा गया है कि गायों को गले लगाने से ''भावनात्मक संपन्नता'' आएगी और ''सामूहिक प्रसन्नता'' बढ़ेगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि वैदिक परंपराएं ''पश्चिमी संस्कृति की प्रगति'' के कारण लगभग ''विलुप्त होने के कगार'' पर हैं और ''पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध ने हमारी भौतिक संस्कृति तथा विरासत को लगभग भुला दिया है।''

इस नोटिस ने जहां सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने इसे विवादित बताते हुए नोटिस को वापस लेने की भी मांग की है। इस बीच, केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि यह सब हमारी परम्पराएं रही हैं और गाय को गले लगाने में कोई हर्ज नहीं है।

वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने भी 14 फरवरी को 'काउ हग डे' मनाने के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी किए गए नोटिस का समर्थन करते हुए कहा है कि सभी को गाय से प्यार करना चाहिए। नोटिस के बारे में पूछे जाने पर गिरिराज सिंह ने कहा, ''यह एक अच्छी पहल है।'' उन्होंने कहा, ''हमें गायों से प्यार करना चाहिए। मुझे खुशी है कि यह मिशन शुरू किया गया है। आपको भी गायों से प्यार करना चाहिए।''

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धरमपाल सिंह ने कहा है कि 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे की बजाय 'गौ माता सम्मान दिवस' मनाने के लिए भारतीय पशु अनुसंधान कल्याण बोर्ड द्वारा आदेश इसलिए जारी किया गया है कि क्योंकि गायें हमारे लिए सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि गायें आर्थिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि शून्य बजट खेती का आधार गोबर और गौमूत्र है। मंत्री ने कहा कि किसी पशुपालक को दूध दुहकर गायों को छुट्टा नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि गाय के दूध के अलावा गोबर और गौमूत्र किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि जहां गौमूत्र खेत के कीटों को नष्ट करता है, वहीं गोबर जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है और यह पर्यावरण अनुकूल है। मंत्री ने लोगों से होलिका दहन में गोबर से बने उपलों का उपयोग करने और गौशालाओं का निर्माण करने के लिए गाय के गोबर के साथ बायोगैस संयंत्र लगाने की भी अपील की।

दूसरी ओर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद एम आरिफ ने सरकार से मांग की है कि 14 फरवरी को 'काऊ हग डे' मनाने की भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की सलाह को वापस लिया जाना चाहिए। माकपा सांसद ने लोकसभा में कहा कि पशु कल्याण बोर्ड ने 'गौमाता को हग करने' का दिन मनाने का सुझाव दिया है। आरिफ ने कहा, ''मुझे विश्वास है कि हजारों आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ता इसका अनुसरण करेंगे।'' सांसद ने व्यंग्यात्मक अंदाज में यह भी कहा कि वित्त मंत्री को पशुधन विभाग के आवंटन में कुछ राशि और जोड़नी चाहिए जो ''गाय को गले लगाने के दौरान चोटिल होने वाले कार्यकर्ताओं के इलाज में काम आएगी।'' उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी ''इस राय पर अमल करना चाहिए या ऐसा संभव नहीं है तो फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को केंद्रीय पशुपालन विकास मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला पर इस तरह के नोटिस को वापस लेने का दबाव बनाना चाहिए।''

उधर, भारत में भले काऊ हग डे को लेकर तमाम तरह के मीम्स बन रहे हैं लेकिन हम आपको बता दें कि पश्चिमी देशों में यह कोई नई बात नहीं है। वहां तनाव और उच्च रक्त चाप से राहत पाने के लिए लोग गाय को गले लगाते हैं। इसके लिए अमेरिका में बड़े-बड़े फॉर्म हाउसों में आयोजन भी किये जाते हैं ताकि लोग आकर गाय को गले लगा सकें। इस बारे में कई अध्ययन भी सामने आये हैं जिनसे पता चलता है कि गाय की धीमी धड़कन, उसके शरीर का गर्म तापमान और उसके शरीर के बड़े आकार के कारण जब कोई इंसान गाय को गले लगाता है तो उसे सुखद अनुभूति मिलती है। अध्ययनों से सामने आया है कि गाय को गले लगाने से रक्तचाप कम होता है और हृदय की गति भी संतुलित होती है।

कुछ मीडिया रिपोर्टों में तो विभिन्न अध्ययनों के हवाले से यहां तक कहा गया है कि मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए गाय को गले लगाना काफी लाभदायक होता है। जहां तक गौमूत्र और गोबर से मानव जीवन को होने वाले आर्थिक और औषधीय लाभों की बात है तो भारत में तो इस बात को लोग प्राचीन काल से मानते ही हैं और अब पूरा विश्व भी इसे मान रहा है।

रमेश सिन्हा छग हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी मार्च में रिटायर हो रहे हैं। अब उनकी जगह इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रमेश सिन्हा नए चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनके नाम का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से ट्रांसफर पर गए जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के साथ ही इलाहाबाद, गुजरात, कोलकाता और मणिपुर और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सीनियर जजों का प्रमोशन करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है।

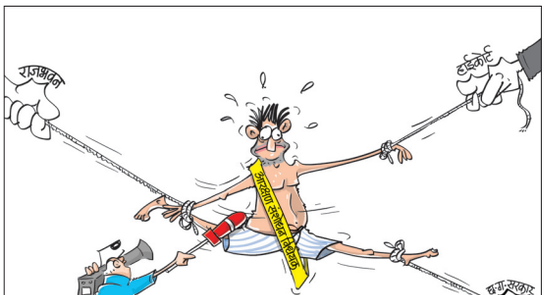

राजभवन को जारी अपनी नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक

1बिलासपुर। आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर दायिर याचिका पर पिछले दिनों राज्यपाल सचिवालय को हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा था पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जारी अपनी नोटिस पर रोक लगा दी है।

उल्लेखनीय है कि सचिवालय की ओर से एक आवेदन गुरुवार को हाईकोर्ट में लगाया गया था जिसमें कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को अपने कार्यालय की शक्तियों और कार्यों को लेकर विशेषाधिकार है। इसके तहत वह किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसके चलते हाईकोर्ट उसे नोटिस जारी कर जवाब नहीं मांग सकता। सचिवालय की ओर से अधिवक्ता बी गोपाकुमार ने कहा कि किसी विधेयक पर कितने दिनों में निर्णय लेना है, इसकी भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। राज्यपाल सचिवालय की ओर से मांग की गई थी कि उक्त नोटिस पर रोक लगाई जाए। गुरुवार को हाईकोर्ट में इस पर बहस हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। शुक्रवार को कोर्ट ने यह माना कि राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है और उसने अपनी नोटिस पर रोक लगा दी।

उल्लेखनीय हैं कि लगभग 2 माह पूर्व छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 32, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग के लिए 27, अनुसूचित जाति के लिए 13 और सामान्य वर्ग से आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए 4 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया है। इसके विरुद्ध अधिवक्ता हिमांग सलूजा की ओर से तथा राज्य शासन की तरफ से अलग-अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई है।

प्रमुख समाचार

वीडियो बनाना कांग्रेस सांसद को पड़ा महंगा, पूरे सत्र के लिए किया गया निलंबित

नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को सदन की कार्यवाही के लिए शेष बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया। उन्होंने सदन के अंदर से एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें विपक्षी सांसदों को धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार की प्रतिक्रिया का विरोध करते हुए देखा गया था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे के बारे में गंभीर विचार व्यक्त किया और इसे अपनी ओर से अवांछित गतिविधि के रूप में वर्णित किया। धनखड़ ने कहा कि कल पब्लिक डोमेन में ट्विटर पर, इस सदन की कार्यवाही से संबंधित एक वीडियो का प्रसार किया गया था ... रजनी अशोकराव पाटिल इस अस्वास्थ्यकर गतिविधि में शामिल थीं और जो देखा गया है वह एक ऐसा मामला है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि विशेषाधिकार समिति मामले की जांच करेगी और पाटिल तब तक निलंबित रहेंगी जब तक समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपती है।

मोदी सरकार में चेहरा देख नहीं होता कोई आवंटन, पहले चलता था जीजा-भतीजा कल्चर

नई दिल्ली। लोकसभा में आम बजट 2023-24 पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 के सार के बारे में बोलते हुए कहा कि यह बजट राजकोषीय विवेक की सीमाओं के भीतर भारत के विकास अनिवार्यताओं की आवश्यकताओं को संतुलित करता है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि करप्शन पर बोलने का कांग्रेस को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अपने कार्यकाल के समय कांग्रेस ने गरीबों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। विपक्षी नेताओं की ओर से यह आरोप लगाने के बाद कि यह बजट अदाणी समूह के लिए ग्रीन बजट है पर वित्त मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि जीजा और भतीजा को फायदा पहुंचाने का कल्चर कांग्रेस सरकार के समय था। मोदी सरकार में यह सब नहीं चलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में कोई भी आवंटन किसी विशेष व्यक्ति को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, बल्कि सभी को ध्यान में रखकर किया जाता है।

दाऊदी बोहरा समुदाय की बहिष्कार प्रथा का मामलानौ जजों की बेंच को रेफर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दाऊदी बोहरा समुदाय की बहिष्कार प्रथा के मामले की याचिका को नौ जजों की बेंच को रेफर कर दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने कहा कि नौ जजों की पीठ सबरीमाला मामले पर फैसला देगी तो वही पीठ दाऊदी बोहरा समुदाय की बहिष्कार प्रथा पर भी फैसला दे। पांच जजों की पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल के अलावा जस्टिस एएस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जेके माहेश्वरी भी शामिल हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान दाऊदी बोहरा समुदाय के वकील ने अपील की कि नौ जजों की बेंच सबरीमाला मामले पर फैसला देगी, ऐसे में इस मामले को भी नौ जजों की पीठ को रेफर करने की मांग की। बता दें कि नौ जजों की पीठ केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को एंट्री देने के मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। साथ ही पीठ तीन और मामलों पर सुनवाई कर रही है, जिनमें महिला अधिकार और धार्मिक मामलों की प्रैक्टिस के अधिकार पर फैसला होना है।

जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरा वुहान

चीन । पिछले साल के आखिर में देश भर में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद से सार्वजनिक असंतोष के नए मामले में हजारों लोगों ने अपने चिकित्सा लाभों में कटौती के विरोध में मध्य चीन में भारी बारिश के बीच प्रदर्शन किया। चीन में जिनपिंग सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। चीन के वुहान में हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग सरकार की मेडिकल इंशोरेंस पॉलिसी से नाराज हैं। पिछले साल के आखिर में देश भर में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद से सार्वजनिक असंतोष के नए मामले में हजारों लोगों ने अपने चिकित्सा लाभों में कटौती के विरोध में मध्य चीन में भारी बारिश के बीच प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में यांग्त्ज़ी नदी के किनारे बसे वुहान शहर में सरकार के खिलाफ रेनकोट और छाता लिए बुजुर्ग प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आ रही है, जबकि पुलिस अधिकारी उन्हें फाटकों के पास जाने से रोकने की कोशिश में लगे दिख रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट को दो नए जज मिले, क्षमता पूरी 34 हुई

नई दिल्ली। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया भारत के संविधान के तहत प्रावधानों के अनुसार, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।सुप्रीम कोर्ट को दो और जज मिल गए हैं. राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर मुहर लगाई है। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत की क्षमता को पूर्ण करते हुए उच्चतम न्यायालय के दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात को ट्विटर पर साझा करते हुए कहा कि दो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत किया गया, जिससे शीर्ष अदालत की कुल शक्ति अधिकतम 34 न्यायाधीशों तक पहुंच गई। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया भारत के संविधान के तहत प्रावधानों के अनुसार, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।

गहलोत ने ऐसे सजाई फील्डिंग

भाजपा की सियासी पिच पर कांग्रेस ने पकड़ी अयोध्या की राह

आशीष तिवारी

राजस्थान में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पेश किए गए बजट में भाजपा की सियासी पिच पर अपनी पूरी फील्डिंग सजा दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने न सिर्फ उज्जवला योजना में लाभार्थियों को पांच सौ में सिलेंडर देने की घोषणा की, बल्कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का पूरा खाका भी अपने इस सियासी बजट में पेश कर दिया। गहलोत के इस कार्यकाल के पेश किए गए आखिरी बजट को राजनीतिक गलियारों में सियासी बजट के तौर पर ही देखा जा रहा है। हालांकि सियासत पर चर्चा इस बात की ज्यादा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही जुबानी जंग और अंदरूनी कलह पर यह बजट कितना भारी होगा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को पेश किए गए बजट में चुनाव की उन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही बड़ा बजट पेश किया, जिसका चुनावी नतीजे पर पूरा असर दिखे। अपने बजट में अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की उन योजनाओं में लाभ से वंचित लाभार्थियों को अपनी सरकार की ओर से न सिर्फ राहत दी, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में एक बड़ा सियासी दांव भी खेला है। अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में राज्य के लोगों को तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए कई नई जगहों को भी जोड़ा है। इसमें अयोध्या भी शामिल है। कांग्रेस की सरकार में अयोध्या और वहां के मंदिर में दर्शन कराने घोषणा से सियासी गलियारों में तमाम कयास भी लगाए जाने लगे। सिर्फ यही नहीं अशोक गहलोत ने अपनी घोषणा में इस बात का भी जिक्र किया कि उज्जवला योजना में जिन लोगों सिलेंडर तो मिल गए लेकिन वह उसे भरवा नहीं पा रहे हैं।

ऐसे परिवारों के लिए 500 रुपये में उनकी सरकार सिलेंडर भी देगी। इसके अलावा अभी तक 50 यूनिट फ्री में दी जाने वाली बिजली को भी 100 यूनिट तक निशुल्क कर दिया है। मेडिकल कॉलेज के खुलने से लेकर युवाओं को रोजगार देने के मामले में अशोक गहलोत ने इस बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएं भी हैं।

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषण एचएन पवार कहते हैं कि अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जो बजट पेश किया, वह इस साल होने वाले विधानसभा के चुनावों के लिहाज से तैयार किया गया है। हालांकि पवार कहते हैं कि अशोक गहलोत के पिछले कुछ बजट को आप देखें, तो वह इस तरह का बजट पहले भी पेश करते रहे हैं। इस साल विधानसभा चुनाव है और सियासत के लिहाज से राज्य के बजट को उसी नजरिए से देखा भी जाता है, इसलिए अशोक गहलोत के बचत, राहत और बढ़त वाले इस बजट को विधानसभा चुनाव वाला सियासी बजट माना जा रहा है। सियासी जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने बजट पेश किया है उसमें उन्होंने राजस्थान कांग्रेस में मचा अंदरूनी विवाद और घमासान को भी बहुत हद तक थामने की कोशिश की है।

दरअसल राजस्थान में शुक्रवार को पेश किए गए बजट को सियासत की नजरों में कई नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक अरुण शर्मा कहते हैं कि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से लोकलुभावन बजट जारी किया है, उससे केंद्रीय नेतृत्व को भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि वह लोगों के लिए एक अच्छा बजट लेकर आए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसी बजट के माध्यम से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को भी एक संदेश दिया है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में चल रही दो नेताओं के बीच की अदावत का बहुत फायदा विपक्ष को नहीं होगा। इसके पीछे तर्क देते हुए वह कहते हैं कि भाजपा के नेताओं के बीच में तो कांग्रेस के नेताओं से भी ज्यादा अदावतें छिड़ी हुई हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में तमाम तरह की निशुल्क योजनाओं के साथ-सथ रियायती योजनाओं की भी झड़ी लगाई। मुफ्त योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि यह फ्रीबीज नहीं हैं बल्कि यह सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से लागू की गई योजनाएं हैं। राजस्थान में राजनीति को करीब से समझने वाले विक्रांत झालावाड़ बताते हैं कि भाजपा ने जिस तरीके से सियासत में अलग-अलग तरह की पिच तैयार की उस पर कांग्रेस ने एक पॉलिटिकल शॉट तो बजट के माध्यम से लगा ही दिया है। विक्रांत के मुताबिक जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई उज्जवला योजना में सिलेंडर पाने वालों को अशोक गहलोत ने पांच सौ रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है। तीर्थ योजना में अयोध्या को शामिल कर वहां के मंदिरों में दर्शन कराने की बात की वह एक तरीके से भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी करने जैसा ही है। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि अपने राज्य के लोगों को दर्शन कराने के लिए वह बीते कई सालों से यह योजना चला रहे हैं। अयोध्या का नाम जोड़ने पर वह कहते हैं कि हर साल नए नए धार्मिक शहर इस योजना में जुड़ते रहते हैं।

राज्य सरकार ने वेतन विसंगति को दूर करने कारगर कदम नहीं उठायाः शिक्षक फेडरेशन

नगरी। सहायक शिक्षक एवं नवीन प्रधानपाठको ने छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय निर्देशानुसार रावणभाठा मैदान नगरी में अनिश्चितकालीन आंदोलन के चौथे दिन छत्तीसगढ़ महतारी एवं भारत माता के पूजा अर्चना,व राजकीय गीत के साथ प्रारंभ किया गया। आज के आंदोलन में वर्तमान भूपेश सरकार के द्वारा पिछले सत्र दिसंबर 2021 में 18 दिनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद कमेटी बनाकर हमारे मुख्य मांग प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन विसंगति को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था। जिसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया और ना ही वेतन विसंगति को दूर किया गया।

सरकार के द्वारा हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ साथियों को प्रधान पाठक बना दिया गया किंतु, उन्हें भी वेतन विसंगति का लाभ नहीं मिला।नवनियुक्त प्रधान पाठक साथी समतुल्य वेतन में आ चुके है।भूपेश सरकार को सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा हमारी मांगों को अभिलंब पूर्ण करने के लिए बार-बार एवं चरणबद्ध आंदोलन किया जा

रहा है किंतु सरकार के द्वारा अभी तक इस हेतु कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।जिससे सहायक शिक्षक फेडरेशन के साथियों में काफी नाराजगी है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी शिक्षकों को आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा। सहायक शिक्षक फेडरेशन/शिक्षक फेडरेशन के सचिव गजानंद सोन,कमलेश चन्द्राकर सहसचिव व बसंत साहू ने बताया कि आज भरत उगेल,नवदीप सलाम,चन्द्रकुमारी नौरंगे,एवं सारे वक्ताओ ने कहा कि आगामी समय में राज्य सरकार को हमारी मुख्य माँग प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन विसंगति दूर करना होगा। क्योंकि इसी सरकार के मंत्री सम्माननीय टी.एस.देव एवं स्वयं मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कहा गया था कि वर्ग 1 एवं 2 के साथियों के वेतन की तुलना में सहायक शिक्षक साथियों के वेतन में भारी असमानता हैं। जिसे छ.ग.कांग्रेस के द्वारा अपने घोषणापत्र में भी प्रमुखता से स्थान दिया गया था। किंतु सरकार बनने के 4 साल पूर्ण होने के बाद भी, सहायक शिक्षक फेडरेशन के मुख्य मांग,प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कोई ठोस कारगर कदम नहीं उठाया गया।आन्दोलन से प्रेरित होकर स्वफूर्त होकर अनुप कुमार ध्रुव ने टीचर्स एसोसिएशन को छोड़कर छ.ग.सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन का सदस्यता ग्रहण किया।

उक्त आंदोलन को शरीफ बिग मिर्जा अध्यक्ष, प्रकाश चंद साहू उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष चैंपेश्वर साहू, शशिकांत बैरागी अध्यक्ष आन्दोलन समिति, टीकाराम कुंजाम,अनिल कुमार साहू अंकेक्षक, ममता प्रजापति अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, कुमारी साहू,स्कंध शेष, राजकुमारी सिन्हा, खंजना कश्यप, रोशन शांडिल्य, टीका राम कुंजाम, सुरेन्द्र प्रजापति के द्वारा आंदोलन को संबोधित किया गया। आज के आंदोलन में निशित सोम, राज कुमार नेताम, सुनील कुमार सिन्हा, कृष्ण कुमार साहू, योगेश्वरी ध्रुव, नीलिमा साहू, अफ्साना खान, मेनका कश्यप, दूज नेताम, लक्ष्मी नेताम, किरण, चन्द्रकला कश्यप, प्रज्ञा बिसेन, शशिकला बैरागी, मनोज देवांगन, माधवी, किरण लता शांडिल्य, उमेश्वरी भंडारी, नरेंद्र कुमार साहू, कैलाश पटेल, दीपक पारिकर, धनंजय साहू, कृष्ण कुमार नेताम, यूरेश झारिया, भगवत दयाल, अनिता दर्रो, जितेन्द्री बघेल, खिलेश्वरी मंडावी, स्नेह लता कुर्रा, आशा सोनी, राजेश यादव, शिवकुमार एवं सभी सकुलों से सहायक शिक्षक, एवं नव नियुक्त प्रधानपाठक साथियों ने आज के आंदोलन में भाग लेकर प्रदेश सरकार को सहायक शिक्षक फेडरेशन/समग्र शिक्षक फेडरेशन की मुख्य मांग प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन विसंगति दूर करने हेतु मांग एवं अपील किया गया हैं। आज के आंदोलन में महिला शिक्षक साथियों द्वारा धरना हड़ताल मंच का संचालन किया।

राज्यपाल सचिवालय को जारी अपनी नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

■ आरक्षण संशोधन विधेयक का मामला

बिलासपुर। आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर दायिर याचिका पर पिछले दिनों राज्यपाल सचिवालय को हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा था पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जारी अपनी नोटिस पर रोक लगा दी है।

उल्लेखनीय है कि सचिवालय की ओर से एक आवेदन गुरुवार को हाईकोर्ट में लगाया गया था जिसमें कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को अपने कार्यालय की शक्तियों और कार्यों को लेकर विशेषाधिकार है। इसके तहत वह किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसके चलते हाईकोर्ट उसे नोटिस जारी कर जवाब नहीं मांग सकता। सचिवालय की ओर से अधिवक्ता बी गोपाकुमार ने कहा कि किसी विधेयक पर कितने दिनों में निर्णय लेना है, इसकी भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। राज्यपाल सचिवालय की ओर से मांग की गई थी कि उक्त नोटिस पर रोक लगाई जाए। गुरुवार को हाईकोर्ट में इस पर बहस हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। शुक्रवार को कोर्ट ने यह माना कि राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है और उसने अपनी नोटिस पर रोक लगा दी।

उल्लेखनीय हैं कि लगभग 2 माह पूर्व छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 32, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग के लिए 27, अनुसूचित जाति के लिए 13 और सामान्य वर्ग से आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए 4 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया है। इसके विरुद्ध अधिवक्ता हिमांग सलूजा की ओर से तथा राज्य शासन की तरफ से अलग-अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई है।

आरईजीएल कंपनी के बाहर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन

■ भू-विस्थापित युवाओं के समर्थन में आए डीडीसी आकाश मिश्रा

रायगढ़। अडानी कंपनी के आरईजीएल कंपनी के बाहर भू-विस्थापित युवा अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के तीसरे दिन क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य आकाश मिश्रा उनके समर्थन में आए। उन्होंने भी युवाओं के प्रदर्शन को उचित बताया। वहीं कंपनी के अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि क्षेत्र के युवाओं की मांगों को कंपनी के पूरा करना ही होगा। यहां के किसानों से अपनी जमीन कंपनी के उद्योग लगाने के लिए दी है। कंपनी में उन्हें कंपनी पे-रोल पर काम दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी। इस दौरान पुसौर तहसीलदार, पुसौर थान प्रभारी सहित अन्य अधिकारी पहुंचे थे। उल्लेखनीय है कि प्रदर्शन कर रहे भू-प्रभावितों ने बताया कि बड़े भंडार में संचालित आरईजीएल कंपनी पहले कोरबा वेस्ट कंपनी थी। उक्त कंपनी के द्वारा उद्योग लगाने के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी। इस समय प्रत्येक जमीन खाता के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन स्थायी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कई बार इसके लिए कंपनी के अधिकारियों से चर्चा की गई, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। इस बात को लेकर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें

आरईजीएल छोटे भण्डार मे भू-अर्जन से प्रभावित लोगों को अदाणी पेरोल पर रखा जाए, सभी भू-अर्जन से प्राभावित लोगो को अदाणी के कर्मचारियों को मिलने वाले बीमा योजना का लाभ मिले। त्रिपक्षीय वार्ता में सभी सम्मिलित बातों का पालन किया जाए। भू विस्थापन से प्रभावित ऐसे लोग जिनको कम्पनी में रोजगार नहीं मिला है उनको भी कम्पनी मे रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जब तक उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब तक वादे के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। आरईजीएल छोटे भण्डार में रिक्त पदों पर पहले प्राथमिकता योग्यता अनुसार भू-अर्जन से प्रभावित लोगों को दी जाए। आस पास के गांव में सीएसआर मद से खेल मैदान, सीसी रोड, सामुदायिक भवन, हॉस्पिटल एवं पानी टंकी का निर्माण जैसा कार्य सी एस आर द्वारा किया जाता है जो वर्तमान में इनका लाभ नहीं मिल रहा है, सभी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। आस पास के परिक्षेत्र में कोयला एवम फ्लाई ऐश के वाहनों के कारण जो प्रदूषण हो रहा है उसका निवारण किया जाए, एवम निरन्तर पानी का छिड़काव किया जाए। प्लांट के आस पास में पौधरोपण का कार्य अधिक से अधिक किया जाए।

भाजपा कांग्रेस एक साथ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी छीनी

■ अविश्वासप्रस्ताव के पक्ष में 23 मत

धमतरी। शुक्रवार को धमतरी जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ सदस्यों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ। अध्यक्ष को इस अविश्वास प्रस्ताव में हार का सामना करना पड़ा,तो वहीं मतदान से पहले ही उपाध्यक्ष अवनेंद्र साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह अब नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है जिसके लिए अब दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।

दरअसल जनपद पंचायत अध्यक्ष गूंजा साहू और उपाध्यक्ष अवनेन्द्र साहू को हटाने के लिए सत्तारुढ़ कांग्रेस और विपक्ष की भाजपा के सदस्य एक होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने कलेक्टर को हस्ताक्षर युक्त पत्र सौंपा था। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के साथ ही भाजपा संगठन की भी नींद उड़ गई। दोनों ही दलों में बैठक का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस हर हाल में अध्यक्ष की कुर्सी बचाना चाहते थे,जबकि भाजपा नेता इस अवसर का लाभ उठाने की पूरी तैयारी में थे।

बता दे कि जनपद पंचायत धमतरी में अध्यक्ष गूंजा साहू कांग्रेस समर्थित तथा उपाध्यक्ष अवनेन्द्र साहू भाजपा समर्थित है। इनके खिलाफ कांग्रेस-भाजपा जनपद सदस्यों में नाराजगी की खबर लंबे समय से सामने आ रही थी।नाराजगी का कारण पंद्राहवे वित्त की राशि को जनपद क्षेत्रों में खर्च को लेकर सहमति नहीं बन पाना है। यहां तक कि कुछ ठेकेदारों से काम कराने को लेकर भी तनातनी भी हो चुकी थी।

गौरतलब है कि जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी निर्वाचन समय से ही विवादों में रही है। 25 सदस्यों वाली इस जनपद में भाजपा सदस्य के क्रॉस वोटिंग करने से कांग्रेस की गूंजा साहू जनपद अध्यक्ष बनने में सफल हो गई थीं। उन्हें 13 वोट मिले थे। इसी तरह उपाध्यक्ष पद पर भी क्रास वोटिंग हुई थी,जिसके सहारे वे उपाध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हुए थे। उन्हें भी 13 वोट मिले थे। तब क्रॉस वोटिंग के चलते दोनों ही दलों का समीकरण बिगड़ा था,जो इसके बाद से यहां कांग्रेस और भाजपा का समीकरण अब तक नहीं बन पाया।

तीन साल बाद फिर से अविश्वास प्रस्ताव का जिन बोतल से बाहर निकला। 15 से ज्यादा जनपद सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौजन्य भेंट के नाम पर कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी से मुलाकात कर अविश्वास प्रस्ताव पत्र सौंपा। कुछ जनपद सदस्यों ने आरोप लगाया था कि जनपद पंचायत धमतरी में विकास कार्यों को लेकर अधिकांश सदस्य संतुष्ट नहीं है। आरोप है कि 15वें वित्त की राशि वितरण व विकास कार्य में भेदभाव किया जाता है। फिलहाल जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर आज मतदान हुआ। अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 23 और विपक्ष में महज 2 मत मिले।

विधायक-मंत्री के लिए बच्चों का उपयोग निंदनीयः अजय

■ विधायक के निर्देश पर अंतिम मूल्यांकन परीक्षा स्थगित करवाकर नेलसनार लाया गया

बीजापुर। युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह ने कहा कि जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा के बीजापुर प्रवास के दौरान कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए स्कूली बच्चों को कलेक्टर-विधायक के निर्देश पर अंतिम मूल्यांकन परीक्षा स्थगित करवाकर नेलसनार लाया गया। उन्होंने कहा कि स्वागत सत्कार करना उनका कर्तव्य था जो उन्होंने किया, उस पर कोई गुरेज नहीं, लेकिन कलेक्टर, विधायक, मंत्री ने जिस तरह अपने स्वागत के लिए स्कूली बच्चों का उपयोग किया वह गलत है।

अजय सिंह ने कहा कि स्कूली बच्चों को स्वागत के लिए लाइन पर खड़ा किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात 11 बजे से बच्चों की परीक्षा थी, मंत्री के स्वागत सत्कार के बजाए शिक्षकों को परीक्षा स्थगित करना पड़ा। 11 बजे से कक्षा 06वीं से कक्षा 09वीं के छात्र-छात्राओं की अंतिम मूल्यांकन परीक्षा थी। विधायक, मंत्री, कलेक्टर, डीईओ को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। उन्होने कहा कि नेलसनार में जब ग्रामीण कार्यकर्ता नदारद थे, तब विधायक ने अपनी लाज बचाने के लिए स्कूली बच्चों का इस्तमाल किया, जो शर्मनाक है, इसकी निंदा करता हूं। बीजापुर विधायक की लोकप्रियता जिस तरह गिर रही है, उसे बचाने के लिए स्कूली बच्चों का उपयोग कर विधायक ने अपनी गरिमा गिरा दी, बच्चों परीक्षा से उन्हें वंचित किया गया। शिक्षक कलेक्टर, डीईओ के निर्देश का पालन करने मजबूर दिखे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जस्टिस रमेश सिन्हा होंगे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी 10 मार्च 2023 को रिटायर हो जाएंगे। उनके रिटायरमेंट के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अनुशंसा किया है। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत हैं। उन्हें वहीं पर चीफ जस्टिस बनाए जाने का अनुशंसा किया गया है। प्रीतिंकर दिवाकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वकालत करते हुए यही से जस्टिस बने थे। कुछ वर्ष पूर्व उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया था। एक वर्ष पहले राज्यपाल अनुसूईया उइके ने न्यायमूर्ति अरूप गोस्वामी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई थी। न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने अंग्रेजी में पद की शपथ ली। इसके साथ ही अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 14वें चीफ जस्टिस बन गए।

अभा बहुभाषीय नाट्य स्पर्धा लोकनृत्य उत्सव आज से

जगदलपुर। श्यामाप्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में अभियान संस्था द्वारा 11 से 14 फरवरी तक आयोजित अखिल भारतीय बहुभाषीय नाट्य स्पर्धा और लोकनृत्य उत्सव बस्तर परब 2023 की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। इसमें देशभर के विभिन्न राज्यों से 11 टीमें भाग ले रहीं हैं, वहीं निर्णायक के रूप में पहली बार एनएसडी दिल्ली से दो सदस्यीय टीम बस्तर पहुंच रही है। इस आयोजन में नाटक सहित लोकनृत्य की भी प्रस्तुति होगी। एनएसडी से आने वाले निर्णायकों में एक ग्वालियर व दूसरे अंबिकापुर और तीसरे जगदलपुर के हिमांशु शेखर झा होंगे। इस दौरान नाट्य परिचर्चा, रंग यात्रा सहित प्रति दिन प्रस्तुतियों के बाद कैन फायर भी लगेगा। शहर में भव्य शोभायात्रा भी निकाली जाएगी। इसमें देशभर से आए कलाकारों द्वारा शहर के मुख्य मार्ग पर अपनी कला का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं शहर में इनका जगह-जगह स्वागत भी किया जाएगा।

सरकारी जमीनों को निजी बताकर बेचा, होगी एफआईआर

कोरबा। फर्जीवाड़ा कर जमीन की खरीदी बिक्री करने वाले दलालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जमीन की खरीदी बिक्री में शामिल भू.माफियाओं पर अब एफआईआर दर्ज किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से जमीन दलालों में हड़कंप मच गया है। सरकारी और आदिवासी जमीनों को निजी बताकर बेचने की शिकायत विभाग को लगातार मिल रही थी। शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की तो कई चौकाने वाले प्रकरण सामने आने लगे हैं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दलालों पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। प्रशासनिक कार्रवाई की भनक लगते ही कई भू.माफिया भूमिगत हो गए हैं। एक मामला डीडीएम रोड में सामने आया है। यहां खसरा नंबर 670/4 आदिवासी भूमि को सामान्य बनाकर ऊंची कीमत में बेच दिया गया है। इसी तरह खसरा नंबर 669 की जमीन को बिना रजिस्ट्री के नामांतरण करा लिया गया। शारदा विहार में खसरा नंबर 384 नंबर की भूमि सीएसईबी की जमीन को निजी बनाकर बेचा गया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह के लिए 18 तक आवेदन आमंत्रित

दंतेवाड़ा। महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कन्याओं के सामूहिक विवाह 21 फरवरी 2023 को सम्पन्न कराया जाना है। योजना के अंतर्गत योजना के तहत कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 से अधिक होनी चाहिए। कन्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत राशन कार्डधारी परिवार की सदस्य होनी चाहिए। वर व वधु का प्रथम विवाह होना चाहिए तभी वह योजना के लिए पात्र होगी। विवाह हेतु पात्रता रखने वाली वर/वधु या उनके परिवार के सदस्य नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक तथा विकासखण्ड के एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय से सम्पर्क कर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर मांगे गए दस्तावेज के साथ 18 फरवरी 2023 तक पूर्ण रूप से भरकर आवेदन पत्र परियोजना कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

मेघा स्कूल के छात्र-छात्राएं परीक्षा पर चर्चा में भाग लिया

धमतरी। शासकीय माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, विद्यालय मेघा छात्र-छात्राएं परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पर दिए गए टिप्स ध्यान पूर्वक सुनते हुए प्रोजेक्टर के माध्यम से अपने समस्या का समाधान किए जिसमें मोदी द्वारा बताए गए टिप्स परीक्षा अपनी क्षमता दिखाने का तरीका है। इसलिए घबराए और भयभीत न हों। सकारात्मक रहें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। अपने दोस्तों से अपनी तुलना मत करें स्वयं पर विश्वास रखें और और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि परीक्षा के अंक ही सब कुछ नहीं होते हैं। टाइम टेबल बनाकर पढाई करें।माता-पिता को सामाजिक स्थिति के कारण बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। साथ ही उन्होंने छात्रों को अपेक्षाओं के किसी भी बोझ से बाहर निकलने के लिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें।जिन विषयों में आप कमजोर हैं, उन पर अधिक फेकस करें और उनकी तैयारी नोट्स बनाकर करें। तैयारी करते समय छात्र नोट्स जरूर बनाएं।

गोबर से बिजली बननी शुरू, पहले दिन चलाए गये संयंत्र के बिजली उपकरण

जगदलपुर। जगदलपुर में शहर के शिवमंदिर वार्ड स्थित बायोगैस संयंत्र में बुधवार को बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। पूरे संभाग में यह पहला मौका है जब गोबर से गैस बनाने का काम इतने व्यापक स्तर पर किया गया है। संयंत्र में जैसे ही बिजली का उत्पादन हुआ तो नगर निगम ने पहली बार संभाग में गोबर से बिजली बनाने का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। गोबर से बिजली बनाने की शुरूआत के दौरान महापौर सफीरा साहू, आयुक्त दिनेश नाग व अन्य जनप्रतिनिधी भी मौके पर मौजूद रहे।

महापौर और आयुक्त ने कहा कि अभी संयंत्र को शुरू किया गया है। पहले दिन ज्यादा बिजली उत्पादित नहीं की गई है,

लेकिन इसकी क्षमता को धीरे से बढ़ाया जायेगा। निगम आयुक्त ने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस संयंत्र से हर दिन दस किलो वाट बिजली पैदा हो। गौरतलब है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) ट्रांबे और कार्तिकेय साराभाई की संस्था सेंटर फार इनवायरमेंट एजुकेशन (सीईई) के तकनीकी मार्गदर्शन में यहां गोबर से बिजली बनाने का काम किया जा रहा है। गोबर से बिजली बनाने के संयंत्र का लोकार्पण 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों किया गया था, लेकिन उस दौरान बिजली का उत्पादन शुरू नहीं किया गया था।

बायोगैस संयंत्र से पहली बार जो बिजली उत्पादित हुई है उससे संयंत्र के बिजली उपकरण ही जैसे पंखे, लाइट, एग्जॉस्ट फेन व अन्य बिजली के उपकरण चलाये गये हैं। जैसे ही संयंत्र से बिजली पैदा हुई और इस बिजली से उपकरण चलने लगे तो यहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर खुशी जाहिर की। अफसरों ने बताया कि अभी ट्रायल के तौर पर बिजली पैदा की गई है। इस संयंत्र की क्षमता हर दिन दस किलो वाट बिजली पैदा करने की है अभी पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन की शुरूआत की जायेगी और यहां पैदा होने वाली बिजली संयंत्र के आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को ही दी जायेगी।

बायोगेस संयंत्र में सबसे पहले सीमेंट से बने इनलेट चैंबर में गोबर और पानी का घोल तैयार किया गया। यह घोल लोहे से ढका हुआ और 15 फीट गहरे बायोगैस संयंत्र में जाता है। गैस एक पाइप के जरिए बायोगैस बैलून में स्टोर होता है। गोबर गैस में मीथेन के अलावा और कई गैस होती हैं। ऐसे में यहां 3 स्क्रबर लगाए गए हैं। इसमें मीथेन गैस को फिल्टर कर अलग किया जाता है। इसके बाद जनरेटर की सहायता से बिजली उत्पादन होता है।

विधायक एवं कलेक्टर ने पाली महोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा

कोरबा। महाशिवरात्रि के अवसर पर पाली में आयोजित होने वाले पाली महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने पाली तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा और कलेक्टर संजीव झा जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ आज केराझरिया स्थित मैदान पहुंचे। पाली महोत्सव आयोजित करने के लिए पाली से लगे केराझरिया में स्थित लगभग दो एकड़ खाली मैदान का चयन किया गया है। महोत्सव स्थल पर पहुंचकर विधायक एवं कलेक्टर ने पूरे स्थल का जायजा लिया। साथ ही कार्यक्रम की रूप रेखा पर विस्तृत चर्चा की। विधायक एवं कलेक्टर ने गरिमामय तरीके से पाली महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने मैदान में

सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए। उन्होंने महोत्सव स्थल की साफ-सफाई, समतलीकरण, मुख्य मंच निर्माण, स्थल के प्रवेश द्वार, वाहन पार्किंग व्यवस्था, चलित शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था की जानकारी लेकर सभी इंतजाम तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही महोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था एवं सुगम आवागमन के लिए निर्धारित रूट भी तय करने के निर्देश दिए। कलेक्टर झा ने कार्यक्रम के दौरान विद्युत व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक साज-सज्जा, माईक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था एवं लाईटिंग के लिए बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के 4,500 कर्मचारियों को नियमित किए जाने के बारे में सूचित किया है। सरकार ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी। इसके बाद गृह मंत्री शाह का आभार जताते हुए केजरीवाल ने कहा कि स्थायी नौकरी से इन हजारों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि सरकार का काम अपने कर्मचारियों और जनता का ख्याल रखना होता है। मैं इन कर्मचारियों की नौकरी पक्की किए जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभारी हूं। इससे पहले केजरीवाल की अध्यक्षता में एनडीएमसी ने 2019 में नौकरी पक्की करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अमित शाह से मुलाकात भी की थी। केजरीवाल ने इस महीने की शुरुआत में आरएमआर कर्मचारियों को नियमित करने के लिए गृह मंत्री को पत्र लिखा था।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में पढ़ा पुराना बजट

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यसभा में शुक्रवार को अपने कार्यकाल का बजट पेश कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिछले साल के बजट की कुछ पंक्तियां पढ़ दी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा कर दिया। विपक्ष लगातार सीएम गहलोत पर आरोप लगा रही है कि उनका बजट लीक हो गया है। दरअसल, सदन में बजट पढ़ने के दौरान करीब 7 मिनट तक सीएम पुराने बजट की पंक्तियां पढ़ते रहें, तभी उनके मंत्री महेश जोशी ने उन्हें रोक दिया। मंत्री ने अशोक गहलोत को कुछ कहा जिसके बाद सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा कर दिया। बजट के दौरान इतनी बड़ी गलती होने के कारण विपक्ष सरकार को घेरने में जुटी हुई है। वहीं, स्पीकर सीपी जोशी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। बीजेपी के विधायक राजेंद्र राठौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज सीएम गहलोत द्वारा पुराना बजट पेश करने से राजस्थान विधानसभा का अपमान हुआ है।

टीपू सुल्तान की नीतियों पर राजनीति करती है कांग्रेस

बेंगलुरू। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने एक और बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में यह चुनाव टीपू सुल्तान बनाम सावरकर के बारे में है। उन्होंने कहा, राज्य में यह चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं, बल्कि सावरकर और टीपू की विचारधाराओं के बीच लड़ा जाएगा। कटील ने कहा मैं सिद्धारमैया को चुनौती देता हूं, आइए हम चर्चा करें कि इस देश को दोनों में से किस देशभक्त की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, उन्हें टीपू जयंती मनाने की अनुमति है, जिसकी इस राज्य में आवश्यकता नहीं है। कटील के बयान के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस टीपू सुल्तान की नीतियों पर राजनीति कर रही है। हम नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार की नीतियों पर राजनीति कर रहे हैं। उनमें बहुत बड़ा अंतर है। नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार मतलब विकास।

ये नई संसद है, विपक्ष बोल नहीं सकता : अधीर रंजन

नई दिल्ली। हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सवाल किए जाने का बचाव करते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि हमें किसी से बदले की भावना नहीं है। राहुल गांधी ने भाषण में जो कहा वह उनके विचार से कुछ नहीं था, बल्कि उन्होंने अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग शोध पत्र द्वारा लगाए गए आरोपों और दावों के आधार पर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार, हम संसद में अपने विचार बिना फिल्टर किए रख सकते हैं। यह दुख की बात है कि राहुल गांधी के विचारों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। राहुल गांधी के मन में किसी से बदले की भावना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यह नई संसद है, मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है; विपक्ष बोल नहीं सकता। मुझे लग रहा है कि संसद भी काम करना बंद कर देगी।

मैं तय करूंगा कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है : कमलनाथ

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि वे चुनाव लड़ेंगे। सौंसर से लड़ेंगे या छिंदवाड़ा से, यह अगले कुछ दिन में तय करेंगे। दरअसल, एक दिन पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। वे एक जगह बंधकर काम करने के बजाय पार्टी को पूरे प्रदेश में मजबूत करना चाहते हैं। कमलनाथ ने शिवपुरी के पोहरी में पत्रकारों से चर्चा में साफ किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 'मैंने पत्रकारों का भोज आयोजित किया था। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की बात निकली, तब मैंने कहा कि सबसे ज्यादा परेशानी तो मुझे है। मैं छिंदवाड़ा (विधानसभा) का नहीं हूं। मेरा गांव और घर छिंदवाड़ा जिले की सौंसर विधानसभा में आता है। सौंसर वाले मुझसे कहते हैं कि आप सौंसर से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? मैं उनसे कहता हूं कि मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है और कम ही लोगों ने सौंसर का नाम सुना होगा।

प्रधानमंत्री ने लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया

स्पीड और स्केल के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है भारत : मोदी

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्रियों और कई प्रमुख उद्योगपतियों के भाग लेने की उम्मीद है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का विचार सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिए दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं, शिक्षाविदों, थिंक-टैंक और नेताओं को एक साथ लाना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभा को संबोधित किया। अवनीश के अवस्थी, सलाहकार, मैं बहुत खुश हूं कि हमें अपने जीवन में इतना बड़ा दिन देखने को मिल रहा है जब आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 आयोजित हो रहा है। यह शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक कदम है। शिखर सम्मेलन ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) और 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को आकर्षित किया है क्योंकि यूपी का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है।

उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता से है। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल के परिणाम नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर जाना जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। डेडिकेटेड फेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र के रास्ते से गुजरात से जुड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च आज सरकार कर रही है और हर वर्ष इसको हम बढ़ा रहे हैं। इसलिए आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के नए मौके बन रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा में भी निवेश के अनेक अवसर हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि ग्रीन ग्रोथ के जिस रास्ते पर

भारत चल पड़ा है उसमें मैं आपको विशेष तौर पर आमंत्रित करता हूं। इस बार बजट में हमने 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन (नियोजित-ऊर्जा-संक्रमण) के लिए रखे हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत स्पीड और स्केल के रास्ते पर चल पड़ा है। बहुत बड़े वर्ग की बेसिक जरूरतों को पूरा कर लिया है। इसलिए एक लेवल ऊपर की सोचने लगा है। यही भारत पर भरोसे का सबसे बड़ा कारण है। हमारे बजट में यही कमिटमेंट साफ-साफ दिखेगा। इस साल पेश हुए बजट में 35 हजार करोड़ रुपये सिर्फ एनर्जी के लिए हैं। ये दिखाता है कि हमारा इरादा क्या है। मिशन ग्रीन हाईड्रोजन। हमारे इसी इरादे को बुलंद करता है। बजट में इससे जुड़ा पूरा ईको सिस्टम विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए।

प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई-सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। वंदे भारत एक्सप्रेस का नया और उन्नत संस्करण मुंबई और सोलापुर और मुंबई और साईनगर शिर्डी के बीच चलेगा। मुंबई-सोलापुर ट्रेन, नौवीं वंदे भारत ट्रेन देश की वाणिज्यिक राजधानी को महाराष्ट्र में कपड़ा और हुतात्माओं के शहर से जोड़ेगी और सोलापुर में सिद्धेश्वर, सोलापुर के पास अक्कलकोट, तुलजापुर, पंढरपुर और पुणे के पास आलंदी जैसे तीर्थस्थलों के लिए तेजी से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार 2 वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गईं। वे मुंबई और पुणे जैसे वित्तीय केंद्रों को हमारी भक्ति के केंद्रों से जोड़ेंगे। इससे कॉलेज जाने वाले और ऑफिस जाने वाले लोगों, किसानों और श्रद्धालुओं को लाभ होगा। वंदे भारत ट्रेन आज के आधुनिक भारत की एक शानदार तस्वीर है। यह भारत की गति और पैमाने का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि बजट में महाराष्ट्र को क्या मिला। लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा। जैसा कि रेल मंत्री और डिप्टी सीएम ने कहा, महाराष्ट्र को कभी भी रेलवे के लिए 13,500 करोड़ रुपये नहीं मिले। पहली बार राज्य में रेलवे के लिए इतनी राशि आवंटित की गई है। इससे पहले मुंबई-सोलापुर और मुंबई-साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह को हरी झंडी दिखाते हुए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साथ 2 वंदे भारत की सौगात, वो भी ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का टर्मिनस बनाने का काम शुरू हो गया है।

प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त अडाणी पर मेहरबान : खड़गे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडाणी समूह के मामले को लेकर केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए और कहा कि पीएम मोदी अपने दोस्त अडानी पर मेहरबान हैं। इस कारण चर्चा नहीं चाहते।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, एलआईसी का पैसा अडाणी की कंपनी में लगा है, उसके नुकसान पर क्या सवाल नहीं होना चाहिए? क्या एसबीआई के अडाणी को दिए गए कर्ज की चर्चा नहीं होनी चाहिए? अडाणी के शेयर एक लाख करोड़ क्यों गिर गए? क्या अडाणी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या अडाणी की कंपनी में लगे एलआईसी के पैसे पर सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या पूछना गलत है कि पीएम मोदी ने अडाणी के एजेंट के तौर पर विदेशों में ठेके दिलवाए?

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमने तो सिर्फ जेपीसी की मांग की है। खड़गे ने कहा कि बैंकों द्वारा अडाणी को दिए गए 82,000 करोड़ लोन के बारे में सवाल पूछा जाना चाहिए लेकिन मोदी और पूरी सरकार संसद में अडाणी शब्द भी नहीं बोलने देती। खड़गे ने कहा कि उन्होंने संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के चुप्पी साधने और मौनी बाबा बनने के चलते ये स्थिति आई है। इसका इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है, लेकिन इसे भी रिकॉर्ड से निकाल दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था 60 साल में इस पार्टी ने कुछ नहीं किया। इसका जवाब देते हुए खड़गे ने कहा, हमसे वो सवाल करते हैं कि 60 साल में क्या किया? लेकिन हमारे सवालों के जवाब नहीं देते।

बता दें कि वित्तीय शोध करने वाली कंपनी हिंडनबर्ग ने 25 जनवरी 2023 को अडाणी ग्रुप के संबंध में 32 हजार शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के बाद मचे हंगामे के बाद संसद में विपक्ष ने भी अदाणी समूह पर जांच की भी मांग की।

विपक्ष का कहना है कि अडाणी समूह को सरकार ने फायदा पहुंचाने के लिए बिना जांच के बैंकों से लोन दिलाने में मदद की। विपक्ष का कहना है कि बैंकों के पैसे और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों के अडाणी समूह में निवेश किए गए पैसों का अब डूबने का खतरा है।

अदाणी मामले में मेरे जेपीसी जांच की मांग करने वाले बयान को हटाया

राज्यसभा में आज भी हंगामों का सिलसिला जारी रहा। बात इतनी बढ़ कई कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी सदस्यों ने बाहर का रुख अपना लिया। राज्यसभा में आज मल्लिकार्जुन खरगे मोदी सरकार पर सबसे ज्यादा निशाने साधे। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि- प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में केवल खुद की तारीफ की। उन्होंने हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बेरोजगारी, महंगाई, अदाणी, रुपये के गिरते मूल्य और अन्य मुद्दों पर बात ही नहीं की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल वे ही इस देश को बचा सकते हैं, यह अहंकार की बात है। केवल यही नहीं मल्लिकार्जुन खरगे ने संसदीय कार्यवाही से अपने शब्दों को हटाए जाने पर नाराजगी जाहिर की।

खेल
प्रमुख समाचार

दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत 300 के पार

नागपुर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 177 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने सात विकेट खोकर 321 रन बना लिए हैं। भारत के पास 144 रन की बढ़त है और रवींद्र जडेजा के साथ अक्षर पटेल क्रीज पर हैं।

नागपुर टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारतीय टीम ने सात विकेट खोकर 321 रन बना लिए हैं। अक्षर पटेल 52 और रवींद्र जडेजा 66 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहली पारी के आधार पर भारत को 144 रन की बढ़त मिल चुकी है। टीम इंडिया के अभी भी तीन विकेट बचे हुए हैं। ऐसे में भारत मैच के तीसरे दिन बड़ा स्कोर बनाना चाहेगा, ताकि उसे मैच की चौथी पारी में बल्लेबाजी न करनी पड़े।

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 177 रन बनाए। 49 रन बनाने वाले मार्नस लाबुशेन टीम के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे। स्टीव स्मिथ ने 37 और एलेक्स कैरी ने 36 रन बनाए। भारत के लिए जडेजा ने पांच और अश्विन ने तीन विकेट लिए। इसके जवाब में भारत ने सात विकेट खोकर 321 रन बना लिए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 120 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल अर्धशतक लगाकर खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉड मर्फी पांच विकेट ले चुके हैं, लेकिन भारत के पास 144 रन की बढ़त हो चुकी है। अगर मैच के तीसरे दिन भारत 50 रन और बना लेता है तो टीम इंडिया आसानी से मैच अपने नाम कर सकती है। रोहित शर्मा ने दमदार बैटिंग की और शानदार शतक जड़ा। इस शतक को जड़ने के साथ रोहित शर्मा के नाम खास रिकॉर्ड भी हो गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। विश्व में ये उपलब्धि हासिल करने वाले कुल चार खिलाड़ी हो हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

उतार-चढ़ाव के बाद 123 अंक फिसल कर बंद हुआ सेंसेक्स

नई दिल्ली। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। शुक्रवार को सेंसेक्स 123.52 अंकों की गिरावट के साथ 60,682.70 और निफ्टी 36.95 अंक फिसलकर 17856.50 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। शुक्रवार के कारोबारी सेशन में सेंसेक्स में 9ब जबकि अदाणी एंटरप्राइजेस के शेयरों में 5ब की गिरावट दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर टाटा मोटर्स और यूपीएल के शेयरों में डेढ़-डेढ़ प्रतिशत की मजबूती दिखी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के शेयर बाजार में मेटल और आईटी सेक्टर के शेयरों पर सबसे अधिक दबाव दिखा। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले के अनुसा तकनीकी रूप से पिछले हफ्ते निफ्टी सूचकांक ने 17650 के पास सपोर्ट लिया हालांकि यह 17900 के महत्वपूर्ण प्रतिरोध के ऊपर बंद होने में असफल रहा। वर्तमान में निफ्टी 20-दिवसीय एसएमए के पास कारोबार करती दिख रही है।

अंबानी ने यूपी में 75,000 करोड़ निवेश का किया ऐलान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमेन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने बड़ी घोषणा की। अंबानी ने कहा कि 2023 के अंत तक यूपी के हर गांव और शहरों में 5जी सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। इसके साथ ही अगले चार सालों में यूपी में हजारों करोड़ निवेश का भी ऐलान किया। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो 2023 के दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के हर शहर और गांव को कवर करने के लिए 5ज के अपने रोल-आउट को पूरा कर लेगा। गौरतलब है कि जियो कंपनी की ट्रू 5जी सेवा देश के 226 शहरों में पहुंच गई है। पिछले दिनों उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून में रिलायंस जिओ ने अपनी 5जी सेवाएं शुरू कीं।

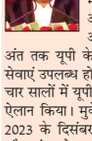

टाटा टियागो इलेक्ट्रिक कार हुई महंगी

नई दिल्ली। देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स की ओर से पिछले साल पेश की गई सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार को खरीदना अब महंगा हो गया है। कंपनी की ओर से कार की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली टाटा की टियागो की कीमत बढ़ गई हैं। कंपनी ने जानकारी दी है कि अब टाटा की टियागो की शुरूआती कीमत में 20 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। कंपनी की ओर से टियागो इलेक्ट्रिक के सभी वैरिएंट्स की कीमतों में बदलाव किया गया है। 19.2 KWH बैटरी पैक और 3.3 किलोवॉट के चार्जर के साथ शुरूआती एक्सई वैरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 8.49 लाख रुपये हो गई है। इसके बाद एक्सटी वैरिएंट की नई कीमत 9.29 लाख रुपये कर दी गई है।

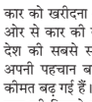

फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च हुआ रियलमी जीटी नियो 5

नई दिल्ली। स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने अपने नए रियलमी जीटी नियो 5 को लॉन्च कर दिया है। इस फोन को फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 प्रोसेसर और 240 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ पेश किया गया है। कंपनी का दावा है कि फोन को 0 से 100 फीसदी तक चार्ज होने में 10 मिनट से भी कम समय लगता है। वहीं फोन 20 फीसदी मात्र 80 सेकेंड में चार्ज हो जाता है। फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ 1.5K डिस्प्ले और दमदार कैमरा भी मिलता है। बता दें कि फोन को फिलहाल घरेलू मार्केट में पेश किया गया है। 240 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ रियलमी जीटी नियो 5 के 16 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज की कीमत CNY 3,199 (लगभग 39,000 रुपये) है। वहीं 16 जीबी के साथ 1 टीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत CNY 3,499 (लगभग 42,600 रुपये) है।

इसरो ने नए रॉकेट एसएसएलवी-डी2 को सफल लॉन्च किया

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को अपने नए और सबसे छोटे रॉकेट एसएसएलवी-डी2 (Small Sataellite Launch Vehicle) को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह लॉन्चिंग की गई। अब खबर आई है कि एसएसएलवी-डी2 ने सफलतापूर्वक तीनों सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने तीनों सैटेलाइट को ऑर्बिट में सही जगह पहुंचाने के लिए टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एसएसएलवी-डी1 के दौरान जब दिक्कतें आईं, हमने उनका विश्लेषण किया और जरूरी कदम उठाए और यह सुनिश्चित किया कि इस बार लॉन्चिंग सफल रहे।

इससे पहले एसएसएलवी-डी2 ने अपने साथ तीन सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष की उड़ान भरी, जिनमें अमेरिकी की कंपनी अंतारिस की सैटेलाइट Janus-1, चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेसकिड्ज की सैटेलाइट ,zaadiSAT-2 और इसरो की सैटेलाइट EOS-07 शामिल थी। ये तीनों सैटेलाइट्स 450 किलोमीटर दूर सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित किए गए।

लोअर ऑर्बिट में लॉन्च करने में काम में लाया जाएगा

इसरो के अनुसार, एसएसएलवी 500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को लोअर ऑर्बिट में लॉन्च करने में काम में लाया जाता है। यह रॉकेट ऑन डिमांड के आधार पर किफायती कीमत में सैटेलाइट लॉन्च की सुविधा देता है। 34 मीटर लंबे एसएसएलवी रॉकेट का व्यास 2 मीटर है। इस रॉकेट का वजन 120 टन है।

बीते साल अगस्त में असफल हो गई थी उड़ान

इस रॉकेट की पहली उड़ान बीते साल अगस्त में असफल हो गई थी। बीते साल एसएसएलवी की पहली उड़ान के दौरान रॉकेट के दूसरे चरण के पृथक्करण के दौरान कंपन महसूस होने के कारण लॉन्चिंग सफल नहीं हो सकी थी। साथ ही रॉकेट का सॉफ्टवेयर उपग्रहों को गलत कक्षा में लॉन्च कर रहा था, जिसके चलते इसरो ने एसएसएलवी की लॉन्चिंग को रद्द कर दिया था।

कुल वजन 175.2 किलोग्राम

एसएसएलवी-डी2 का कुल वजन 175.2 किलोग्राम है, जिसमें ईओस सैटेलाइट का वजन 156.3 किलोग्राम, Janus-1 का वजन 10.2 किलोग्राम और AzaadiSat-2 का वजन 8.7 किलोग्राम है। इसरो के अनुसार, एसएसएलवी रॉकेट की लागत करीब 56 करोड़ रुपए है।

इस साल कई मिशन को अंजाम देगा

इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि फिलहाल हम जीएसएलवी मार्क 3 की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं। जीएसएलवी मार्क 3 वन वेब इंडिया की 236 सैटेलाइट को एकसाथ लॉन्च करेगा। यह लॉन्चिंग मार्च महीने के मध्य में होगी। इसके अलावा इसरो पीएसएलवी-सी55 के प्रक्षेपण की भी तैयारियों में जुटा है। मार्च के अंत तक यह लॉन्चिंग हो सकती है। इसरो चीफ ने बताया कि हम रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग पर भी काम कर रहे हैं। वर्तमान में एक टीम चित्रदुर्ग में लैंडिंग साइट पर मौजूद है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सबकुछ ठीक रहा तो अगले कुछ दिनों में हम लैंडिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। एस सोमनाथ ने कहा कि इस साल कई सारे मिशन होने हैं। खासकर गगनयान कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं।

भारत के न्योते पर मुश्किल में फंसा पाकिस्तान

केएस तोमर

इस साल के अंत में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए चार और पांच मई, 2023 को गोवा में विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत द्वारा हाल ही में भेजे गए आमंत्रण ठुकराने को लेकर पाकिस्तान मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि उसका यह कदम चीन को नाराज कर सकता है, जो रूस के साथ एससीओ का सह-संस्थापक है। दूसरी तरफ अगर वह आमंत्रण स्वीकार करता है, तो वहां के कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिलने की आशंका है, जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक संकट और आगामी चुनावों में इसका फायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गंभीर संकट में हैं, इसलिए उन्होंने माना है कि आईएमएफ की पूर्व शर्त कल्पना से परे है, लेकिन मुल्क को आर्थिक पतन से बचाने के लिए उन्हें इससे सहमत होना पड़ेगा, जो विपक्ष और कट्टरपंथियों को उन्हें घेरने का मौका दे सकता है। लेकिन विदेश मंत्रियों की बैठक के निमंत्रण को स्वीकार करने से एक सकारात्मक अंतरराष्ट्रीय छवि बन सकती है और पाकिस्तान में लोग इससे विमुख नहीं होंगे, जैसा कि अतीत में भी देखा गया है। कूटनीति में, किसी भी शत्रुतापूर्ण राष्ट्र के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए एक कदम आगे या पीछे करना हमेशा तर्कसंगत होता है। भारत ने इसी सिद्धांत पर काम किया है और एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान की भागीदारी चाहता है, जो भारत की अध्यक्षता में हो रही है।

एससीओ बैठक की तैयारी एक बोझिल कवायद है और रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और पर्यावरण मंत्रियों जैसे नौ देशों के अन्य मंत्रिस्तरीय प्रमुख भी एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए मार्च, 2023 से व्यापक चर्चा करेंगे। विश्लेषकों का कहना है कि एससीओ सदस्य सितंबर, 2022 की बैठक के प्रस्तावों को आगे बढ़ाएंगे और क्षेत्र और दुनिया के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दों पर विचार करेंगे। यह तय है कि सदस्य राष्ट्र ड्रग्स के खतरे, कट्टरता, मानव संकट और काबुल शासन की महिला विरोधी मानसिकता, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण ट्रांजिट कॉरिडोर और तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एससीओ विशेषज्ञों की राय है कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है, जो संघर्षों को दूर कर सके। एससीओ और ब्रिक्स के साथ इंटरबैंक कंसोर्टियम (जो अभी सदस्यों के विचाराधीन है), आम वित्तीय कमी की समस्या को हल कर सकता है। एससीओ एकमात्र ऐसा संगठन है, जिसने अपने आंतरिक मतभेदों के बावजूद, वर्तमान विश्व व्यवस्था में अपनी प्रासंगिकता कुछ हद तक बनाए रखी है। यह उस मूल्य को प्रदर्शित करता है, जो प्रत्येक सदस्य संगठन में रखता है। और उनके हितों के टकराव को देखते हुए, यह हाल के दिनों में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता प्रतीत होता है। ब्रेजिंस्की थ्योरी के अनुसार, जो देश मध्य एशिया पर हावी है, वह यूरेशिया पर हावी है, और जो यूरेशिया पर हावी है, वह दुनिया पर हावी है। एससीओ के गठन के बाद से ही चीन और रूस ने इस पर ध्यान दिया है। शंघाई फाइव ने वास्तव में मानवीय आधार पर और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अन्य देशों में हस्तक्षेप का विरोध किया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने की पहल की है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एससीओ बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया जा सकता है, जो भविष्य में बातचीत की बहाली की दिशा में माहौल बनाने का अवसर प्रदान कर सकता है। भारत ने शरीफ के इस बयान का संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने साहसपूर्वक यह स्वीकार किया कि भारत के साथ दशकों तक दुश्मनी करके और तीन युद्ध लड़कर पाकिस्तान ने सबक सीख लिया है, इसलिए अब अपने पड़ोसी के साथ वार्ता की मेज पर बैठकर शांति चाहता है।

अमित शाह का आपरेशन बिहार

अजय सेठिया

जैसी उम्मीद थी, बिलकुल वैसा ही होना शुरू हो गया है। अमित शाह ने नीतीश कुमार को दगाबाजी का सबक सिखाने के लिए उन्हें राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की ठान ली है। अपनी रणनीति के तहत उन्होंने उन्हीं की पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा की पीठ पर हाथ रख दिया है। बिलकुल वैसे ही जैसे भाजपा को महाराष्ट्र में दगा देने वाले उद्धव ठाकरे को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने के लिए एकनाथ शिंदे के सिर पर हाथ रखा था। उपेंद्र कुशवाहा 19 फरवरी को जदयू को तोड़ कर बाहर निकल आएंगे। उनके साथ जदयू के कई सांसद और विधायक भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं। इसके संकेत उपेन्द्र कुशवाहा ने कुछ दिन पहले यह कहते हुए दिए थे कि जदयू में जो जितना बड़ा नेता है, वह उतना ही ज्यादा भाजपा के संपर्क में है। उपेन्द्र कुशवाहा ने 19 फरवरी को पटना में अपने समर्थकों की बैठक बुला ली है, जो दो दिन तक चल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के सामान्य नेता नहीं हैं, वह 12 प्रतिशत वोटों वाले कुशवाहा समाज के निर्विवाद लीडर हैं, जबकि नीतीश कुमार के कुर्मी समाज के वोट सिर्फ दो प्रतिशत हैं। नीतीश कुमार और उपेन्द्र कुशवाहा के गठबंधन को ही बिहार में लव-कुश गठबंधन कहा जाता है। नीतीश कुमार की जाति के ही दूसरे दबंग नेता आरसीपी सिंह पहले ही नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं। भाजपा का नया फार्मूला आरसीपी सिंह और उपेन्द्र कुशवाहा को मिलाकर बिहार के लव-कुश गठबंधन को अपने पक्ष में करना है। रामजन्मभूमि मन्दिर वाली राम की पार्टी भाजपा ने अब लव-कुश का वनवास खत्म करके उन्हें राजभवन में वापस लाने की रणनीति बनाई है। 2014 में लव यानि कुर्मी यानी नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे, लेकिन कुश यानी कुशवाहा एनडीए में थे, तो नीतीश कुमार की जदयू को सिर्फ 2 लोकसभा सीटें मिली थीं। जबकि भाजपा को 22 और कुशवाहा को 3 लोकसभा सीटें मिल गई थीं। एनडीए गठबंधन के तीसरे दल राम विलास पासवान की लोजपा को भी 6 सीटें मिल गई थी। दलित और कुशवाहा वोटों के साथ एनडीए ने 40 में से 31 सीटें जीत लीं थी। 2019 में उपेन्द्र कुशवाहा की जगह पर नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, तो भाजपा और कुशवाहा दोनों को नुकसान उठाना पड़ा था। नीतीश कुमार के चलते 2019 में एनडीए की सीटें तो बढ़ कर 39 हो गई, लेकिन उस का फायदा नीतीश कुमार को हुआ। गठबंधन के कारण भाजपा 30 की बजाए सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ी। उसने सारी सीटें जीतीं, फिर भी उसकी 5 सीटें तो घट ही गईं। वहीं कुशवाहा की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। मोदी के कंधों पर सवार हो कर नीतीश कुमार की जदयू 2 सीटों से बढ़ कर 16 पर गई, जबकि तीन साल बाद ही वह एनडीए को छोड़ कर फिर यूपीए के पाले में चली गई। 2019 में नीतीश कुमार के कारण कुशवाहा का भाजपा से गठबंधन टूटा था। 2020 में नीतीश कुमार के कारण चिराग पासवान का भाजपा से गठबंधन टूट गया। लेकिन यह भी सच है कि चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार की पार्टी विधानसभा में सिर्फ 41 सीटों पर सिमट गई। इसका मतलब यह है कि वोटों के मामले में उपेन्द्र कुशवाहा और चिराग पासवान की ताकत नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा है। लब्बोलुवाब यह है कि आरसीपी सिंह और उपेन्द्र कुशवाहा का नया लव कुश गठबंधन बनाकर और चिराग पासवान को वापस एनडीए में लाकर अमित शाह की रणनीति नीतीश कुमार को राजनीति के हाशिए पर फेंकने की है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भाजपा आरसीपी सिंह और उपेन्द्र कुशवाहा को साथ ला सकेगी।

अगर उपेन्द्र कुशवाहा 20 फरवरी को अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने का एलान करते हैं, तो क्या आरसीपी सिंह भी उस पार्टी में शामिल होंगे। यह तो तय है कि उपेन्द्र कुशवाहा भाजपा में शामिल नहीं होंगे, उसका न उन्हें कोई फायदा होगा, न भाजपा को। इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार के अलग होने से भाजपा दबाव में है, उपेन्द्र कुशवाहा इसी का लाभ उठाकर भाजपा से मोलभाव करने के लिए अपनी पार्टी ही बनाएंगे। भाजपा भी यही चाहती है, ताकि नीतीश कुमार के सामने अति पिछड़ी जातियों का गठबंधन खड़ा करके उन्हीं के हथियार से उन्हें मारें।

1994 में जब जार्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी बनाई थी तो नीतीश कुमार और उपेन्द्र कुशवाहा उनके साथ समता पार्टी में शामिल हुए थे। जिसका बाद में शरद यादव के जनता दल में विलय हो कर जदयू बना। नीतीश कुमार जिनके कंधों पर सवार हो कर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ें, बाद में उन सभी को धोखा दिया। जिस जार्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री और पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, उन्हीं नीतीश कुमार ने 2009 में जार्ज फर्नांडिस का लोकसभा का टिकट काट दिया था। शरद यादव का बाद में नीतीश कुमार ने क्या हाल किया, वह बहुत पुरानी बात नहीं है।

उपेन्द्र कुशवाहा के साथ भी नीतीश कुमार ने वही किया। 2021 में उन्हें पार्टी में शामिल करवाया और पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जब नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ कर महागठबंधन की सरकार बनाई तो उपेन्द्र कुशवाहा को पूछा तक नहीं। कुशवाहा यह मानकर चुप रहे कि कुशवाहों का 12 प्रतिशत वोट होने के कारण उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ़ कह दिया कि दूसरा उपमुख्यमंत्री नहीं बनेगा।

वैसे उपेन्द्र कुशवाहा का भी नीतीश कुमार की तरह पाला बदलने का पुराना इतिहास रहा है। साल 2005 में जब बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की अगुआई वाली एनडीए बिहार की सत्ता में आई, तब कुशवाहा अपनी ही सीट से चुनाव हार गए थे। जिसके बाद कुशवाहा और नीतीश के बीच दूरियां आ गईं। उन्होंने जदयू को अलविदा कह कर अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी बनाई। हालांकि साल 2010 में एक बार फिर बदलाव की बयार बही और नीतीश के न्योते पर कुशवाहा ने घर वापसी की। साल 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उपेन्द्र कुशवाहा ने मार्च 2013 में एक बार फिर अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) बना ली।

2014 के लोकसभा चुनाव में जब जदयू ने एनडीए छोड़ दिया था तो उपेन्द्र कुशवाहा ने भाजपा के साथ गठबंधन करके तीन सीटों पर चुनाव लड़ा और तीनों जीतीं। नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ करने में उपेन्द्र कुशवाहा की अहम भूमिका थी। इसके इनाम में मोदी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में मानव संसाधन राज्य मंत्री बनाया। 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ कर 2 सीटें जीतीं। 2014 से 2018 तक केंद्र में मंत्री रहे, तब तक नीतीश वापस एनडीए में आ चुके थे। लोकसभा सीटों के बंटवारे पर एनडीए से विवाद हुआ, तो उन्होंने केंद्र से मंत्री पद छोड़ कर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन कर लिया था। लेकिन वह खुद और उनकी पार्टी के सारे उम्मीदवार चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव 2019 की करारी हार से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) अध्यक्ष अभी उबरे भी नहीं थे कि पार्टी के दोनों विधायकों ने विधायक दल का नीतीश की पार्टी जदयू में विलय कर दिया। पार्टी के दोनों विधायक ललन पासवान और सुधांशु शेखर जदयू में शामिल हो गए। फिर 2021 में नीतीश कुमार उपेन्द्र कुशवाहा को जदयू में दुबारा ले आए थे। अब दोनों की राह फिर अलग हो गई है।

प्रसंग

भगवान कौन?

बात उस समय की है जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी निच्चेगोंड के गांधी आश्रम में काम करते थे एक बार अनावृष्टि के कारण अकाल की स्थिति आ गयी। तब आश्रम में हर गुरुवार को सस्ते मूल्य पर अनाज बेचा जाने लगा।

एक दिन राजाजी के पास दो ग्रामवासियों के बारे में यह शिकायत आयी कि उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़कर ताड़ी पी है, किन्तु उन्हें संदेह हुआ कि वे झूठ बोल रहे हैं, किन्तु उनसे सत्य बात कैसे उगलवायी जाए? उनके एक साथी ने भगवान की शपथ लिवाने की सलाह दी, किन्तु राजाजी को इस पर विश्वास न हुआ। अकस्मात उनकी दृष्टि एक की चप्पल पर गयी और उन्होंने कुछ सोचकर एक से प्रश्न किया, तुम मोची हो न?

हां, हम दोनों मोची ही है। उसने उत्तर दिया।

तब तो तुम्हारा जीवन चमड़े से ही चलता होगा। तुम्हारी रोजी-रोटी देने वाला यह चमड़ा ही है, इसलिए इस चप्पल को स्पर्श कर कहो कि तुमने ताड़ी पी है या नहीं। और उन दोनों को कबूल करना पड़ा कि उन्होंने रात को ताड़ी पी थी।

राजाजी सोचने लगे- मैं तुझे पैर की जुती समझता हूं- ऐसा कहने वाले लोग जूते को तुच्छ, निकम्मी वस्तु मानते हैं, लेकिन वही जूता न मालूम कितने लोगों को जीवन देता है और उसी से लाखों मनुष्य आजीविका कमाते हैं। फिर भगवान आखिर है कौन? - जो हमारा भरण-पोषण करे, हमारे जीवन को धारण करे, वही तो भगवान है।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

1933 गांधी जी के साप्ताहिक प्रकाशन हरिजन का पहला अंक पुणे से प्रकाशित।
1956 ब्रिटेन के दो राजनयिक जो पांच वर्ष पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे, सोवियत संघ में दोबारा दिखे।
1963 वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध से पहले सोवियत संघ ने भारत को 12 मिग लड़ाकू विमान देने का जो वादा किया था, उसकी पहली खेप के तौर पर चार विमान बम्बई (अब मुंबई) पहुंचे।
1977 देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद का निधन।
1979 आयतुल्लाह खामेनी के समर्थकों ने ईरान की राजधानी तेहरान पर कब्जा किया। सेना अपनी बैरकों में वापस लौट गई और मौजूदा शासन को बचाने के लिए हथियार उठाने से इंकार कर दिया।
1990 दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध करने वाले महान नेता नेल्सन मंडेला को कैद से रिहा किया गया।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

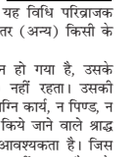

पैङ्गलोपनिषद् (भाग-10)

गतांक से आगे...

तत्पश्चात् वह अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस और अगन्धवत् होकर अव्यय, अनादि, अनन्त, महत् से भी परे, ध्रुव, निर्मल तथा निरामय ब्रह्म ही शेष बचता है। इसके बाद पैङ्गल ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पुनः प्रश्न किया कि ज्ञानियों के कर्म कौन से हैं और उनकी स्थिति कैसी होती है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि जो मुमुक्षु अमानित्व आदि गुणों से सम्पन्न होता है, वह अपनी इक्कीस पीढ़ियों को तार देता है और ब्रह्मविद् हो जाने मात्र से वह अपने कुल की एक सौ एक पीढ़ियाँ तार देता है।

अपनी आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथि तथा मन को ही लगाम जानना चाहिए। इन्द्रियों को अश्व कहा गया है, जो अपने विषय रूपी मार्ग पर गमन करते हैं, परन्तु मनीषियों का हृदय विमान के समान इन सबसे ऊपर उठा हुआ होता है।

महान् ऋषियों का कथन है कि यह आत्मा, इन्द्रिय और मन से युक्त होकर भोक्ता बनता है, इसके बाद हृदय में साक्षात् नारायण प्रतिष्ठित होते हैं।

प्रारब्ध कर्मों के क्षय होने तक जीव, सर्प के केंचुल बदलते रहने की तरह अन्य शरीर धारण करता रहता है; किन्तु अनिकेतन (एक ग्राम में एक रात्रि ही निवास करने वाला परिव्राजक) और मुक्त पुरुष आकाश में चन्द्रमा के समान सर्वत्र सञ्चरित होता रहता है।

ज्ञानी पुरुष तीर्थ में शरीर त्याग करे अथवा चाण्डाल के घर में, प्राणों को छोड़कर वह सदा कैवल्य को ही प्राप्त होता है। शरीर त्याग के पश्चात् उसके शरीर की चाहे दिशाओं को बलि दे दी जाए अर्थात् खुले में डाल दिया जाए अथवा खोदकर जमीन में गाड़ दिया जाए (वह कैवल्य को ही प्राप्त करता है)। यह विधि परिव्राजक (संन्यासी) के लिए है, इतर (अन्य) किसी के लिए कभी नहीं।

जो संन्यासी ब्रह्ममलीन हो गया है, उसके निमित्त अशौच (सूतक) नहीं रहता। उसकी आत्म शान्ति के लिए न अग्नि कार्य, न पिण्ड, न तर्पण और न ही पर्व पर किये जाने वाले श्राद्ध (पार्वण) आदि की ही आवश्यकता है। जिस प्रकार जले हुए को जलाया नहीं जाता और पके हुए को पुनः पकाया नहीं जाता, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि से दग्ध (संन्यासी) के लिए न कोई श्राद्ध आवश्यक है और न ही कोई क्रिया-कर्म। जब तक सांसारिक उपाधियाँ हैं, तब तक गुरु की शुश्रूषा (सेवा) करनी चाहिए। गुरु के समान ही गुरु पत्नी और गुरु सन्तानों के प्रति भी सम्मान पूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

क्रमशः...

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय

डॉ. राकेश मिश्र

अपने उच्च विचारों, आदर्शों और त्याग के कारण भारत के लोगों के हृदय में स्थान बनाने वाले और एकात्म मानववाद जैसी विचारधारा और राष्ट्रवादी चिंतन देनेवाले, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ व राष्ट्रीय जनसंघ के संस्थापकों में शामिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता भारत के सबसे तेजस्वी एवं यशस्वी चिंतकों में से एक रहे हैं।

25 सितम्बर सन् 1916 को चंद्रभान, फुराह, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। 1937 में कानपुर में अपनी बी.ए. की पढ़ाई के दौरान वे अपने सहपाठी बालूजी महाशब्दे और सुंदर सिंह भंडारी के साथ मिलकर समाज सेवा करने लगे। इन्ही दिनों वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार जी व भाऊराव देवरस जी से संपर्क में आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर संघ से जुड़ गए। संघ की शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वे 1939 में संघ के 40 दिवसीय नागपुर शिविर का हिस्सा बने।

भाऊराव देवरस से प्रेरणा पाकर सन 1947 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लखनऊ में राष्ट्रधर्म प्रकाशन स्थापित किया, जिसके अंतर्गत मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म प्रकाशित एवं प्रसारित की जाने लगी। बाद में पांचजन्य साप्ताहिक और दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का भी प्रकाशन यहां से हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक अच्छे साहित्यकार व लेखक भी थे। 1946 में जब संघ से जुड़े किशोरों तक अपनी विचारधारा सरल शब्दों में पहुंचाने की बात आयी तो पंडित जी ने बिना किसी से कुछ कहे रातभर जागकर चाणक्य और सम्राट चन्द्रगुप्त को केंद्र में रखकर सम्राट चन्द्रगुप्त नाम से एक उपन्यास लिख डाला। अगली सुबह जब उन्होंने यह पुस्तक भाऊराव को दी तो सभी आश्चर्यचकित थे। इस उपन्यास की सफलता के बाद युवाओं के लिए भी कुछ ऐसे ही लेखन की मांग उठी। तब उन्होंने जगद्गुरु शंकराचार्य नाम से अपना दूसरा उपन्यास लिखा। 21 अक्टूबर सन् 1951 में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की तो 1951 से 1967 तक वे भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। 29 दिसम्बर 1967 को उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। विडम्बना ही कही जायेगी कि पंडित सिर्फ 44 दिनों तक ही बतौर अध्यक्ष कार्य कर पाए।

भारत को जासूसी गुब्बारों की जरूरत

आदित्य रामनाथन

अमेरिका में चीन के स्पाई बलून को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में खटास और बढ़ गई है। 4 फरवरी को अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान एफ-22 से चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। चीन के जासूसी गुब्बारे यानी चीनी एयरशिप की जानकारी 3 फरवरी को सामने आई थी। चीन ने कहा कि यह गुब्बारा मौसम से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए छोड़ा गया था। चीन के इस गुब्बारे में कुछ अनयूजुअल चीजें थीं। गुब्बारे की दिशा और इसे रफ्तार देने के लिए इसमें एक मोटर और प्रोपेलर लगा था, एक बड़ा पेलोड भी था। चीन का गुब्बारा साइंटिफिक रिसर्च के काम आ रहा था या जासूसी में इस्तेमाल हो रहा था, यह तय करना मुश्किल हो सकता है।

अमेरिका जिन चीजों को 'अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनॉमेना' यानी यूएपी कहता है, उसका ताल्लुक हो सकता है कि चीनी एयरशिप से भी हो। अक्सर सेंसर के ठीक से काम नहीं करने या ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण भी कई चीजों को 'क' करार दिया जाता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि ऐसे यूएपी के दायरे में कई एयरशिप भी हों। पेंटागन की एक हालिया रिपोर्ट में साल 2022 में बलून या बलून जैसी 163 चीजें अमेरिका में दिखने की बात की गई है। साल 2020 में इसी तरह का एयरशिप उत्तरी जापान में देखा गया था। साल 2022 में पोर्ट ब्लेयर के पास इसी तरह का एयरशिप दिखा था। भारत का यह इलाका सामरिक रूप से बेहद अहम है।

जासूसी गुब्बारे कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, जो स्पाई सैटलाइट नहीं कर सकते। सैटलाइट अपनी ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। ऑर्बिट का पहले से अनुमान लगाया जा चुका होता है। विकसित देशों के पास कई दशकों से यह क्षमता है कि वे अपने सैटलाइट की अधिकतर गतिविधियां छिपा सकते हैं। सैटलाइट को इधर-उधर मूव कराया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत फ्यूल खर्च होगा। यह ईंधन बहुत कीमती होता है। इसे ज्यादा अहम जरूरतों के लिए बचाया जाता है। दूसरी ओर, जासूसी गुब्बारे या एयरशिप को दूसरे देश के आसमान में उड़ाना रिस्की तो होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में इन्हें आसानी से मूव कराया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बाधा नहीं आती। एयरशिप या जासूसी गुब्बारे किसी भी सैटलाइट या एयरक्राफ्ट के मुकाबले सस्ते होते हैं। इन्हें बहुत ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है। इस तरह ये एयर टु एयर और सर्फेस टु सर्फेस मार करने वाली मिसाइलों की रेंज से बाहर निकल सकते हैं। जासूसी गुब्बारे किसी भी इलाके पर बहुत देर तक उड़ान भर सकते हैं। लिहाजा विरोधी देश की नौसेना की हरकतों पर नजर रखने में ये काफी कारगर साबित होते हैं। जासूसी गुब्बारे या एयरशिप में स्टेल्थ टेक्नॉलजी का इस्तेमाल करने पर इन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाता है।

भारत की बात करें तो सीमा पर बेहतर तरीके से निगरानी करने में एयरशिप या जासूसी गुब्बारे बहुत उपयोगी हैं। भारत की थल और जल सीमा पर ये एयरशिप तस्करों की हरकतों पर नजर रख सकते हैं। साथ ही, ये मुश्किल में फंस जाने वाली फिशिंग बोट्स को तलाशने में मददगार होंगे। समुद्री निगरानी में एयरशिप का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। इनके जरिए शांति काल में जहाजों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकती है। वहीं, तनाव के हालात में भी इनके चलते युद्ध भड़कने का खतरा कम ही रहता है। साल 2019 और 2020 में इंडोनेशिया के मछुआरों ने अपने देश की समुद्री सीमा में चीन के दो सी विंग अनक्रूड अंडरवॉटर वीइकल्स यानी यूयूव्ही को पकड़ा था। ये चीन के सर्वे शिप्स ने छोड़े थे। समुद्र के भीतर करीब दो महीने समय बिताने के बाद इन यूयूव्ही को आमतौर पर वापस कलेक्ट कर लिया जाता है। ऐसा ही एक सर्वे शिप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के आसपास साल 2019 में दिखा था। वह भारत के एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन में चला आया था। उसे तुरंत वहां से निकलने का आदेश दिया गया था।

हो सकता है कि ऐसे उपकरणों से साइंटिफिक रिसर्च हो की जाए, लेकिन इनका दोहरा इस्तेमाल भी हो सकता है। चीन समुद्र में अपनी क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है। वह एंटी-सबमरीन क्षमता बढ़ाना चाहता है। इसमें समुद्र की सतह, समुद्र के विभिन्न हिस्सों के पानी में नमक की मात्रा और समुद्र के तापमान आदि की जानकारी बेहद काम की होती है।

ऐसा भी नहीं है कि इस तरह के दोहरे इस्तेमाल वाले यूयूव्ही का सहारा केवल चीन लेता है। साल 2016 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने फिलीपींस के पास एक अमेरिकी यूयूव्ही को पकड़ा था। हालांकि अमेरिका ने जब विरोध जताया तो चीन ने उसका यूयूव्ही उसे लौटा दिया। भारतीय नौसेना भी छह सर्वे शिप का इस्तेमाल करती है। ऐसे चार और जहाज नौसेना को जल्द मिलने वाले हैं। ये शिप रिमोटली ऑपरेटेड और ऑटोनॉमस, दोनों तरह के यूयूव्ही का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अभी इनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

जासूसी के दूसरे उपकरणों के चलते भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी होती रहेंगी। सरकारें और आतंकवादी, दोनों ही सस्ते कमर्शल ड्रोन और जासूसी गुब्बारों का सहारा ले सकते हैं। इसे देखते हुए भारत को स्पेशल जैमर डिवेलप करने होंगे। इसके साथ ही सस्ते ड्रोन को मार गिराने का ऐसा तरीका भी निकालना होगा, जिसमें ज्यादा खर्च न आए। हाई एंड एयर टु एयर मिसाइलों का इस्तेमाल महंगा पड़ता है। अंतरिक्ष में भी जासूसी की तमाम हरकतें हो सकती हैं। चीन के पास रांदेवू एंड प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस (RPO) सैटलाइट हैं। ये दूसरे सैटलाइट के काफी करीब पहुंच सकते हैं। आरपीओ का उपयोग रिपेयरिंग और रीफ्यूलिंग जैसे कामों में होता है, लेकिन इनका इस्तेमाल दूसरे स्पेसशिप या सैटलाइट से मिलने वाली जानकारी को बीच में ही इंटरसेप्ट करने या सैटलाइट को नुकसान पहुंचाने में भी हो सकता है। आरपीओ से निपटने के लिए भारत को अंतरिक्ष में अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। भारत को ऐसे तमाम जासूसी उपकरणों के इस्तेमाल में महारत हासिल करनी होगी ताकि विरोधियों को करारा जवाब दिया जा सके।

गांधी आज

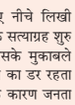

सामुदायिक सत्याग्रह

कहीं भी सामुदायिक सत्याग्रह करने के लिए नीचे लिखी अनुकूलता आवश्यक है। इनके अभाव में सामुदायिक सत्याग्रह शुरु करने में मारकाट मच जाने से आपस में और जिसके मुकाबले सत्याग्रह शुरु किया गया हो उससे बैर-विरोध बढ़ने का डर रहता है और संभव है आखिर में बल प्रयोग या दमन के कारण जनता भयभीत हो जाए तथा और ज्यादा दब जाए।

सत्याग्रह शुरु करने की इच्छा रखने वाले नेताओं में परस्पर संपूर्ण विश्वास और विचारों की एकता होनी चाहिए। यदि एक दूसरे की ईमानदारी पर शंका या नेता की विचारधारा पर अविश्वास या अर्द्धविश्वास हो तो इसे सामुदायिक सत्याग्रह के लिए प्रतिकूल परिस्थिति समझना चाहिए। यदि सत्याग्रह चलाने की इच्छा रखने वाले नेताओं में भिन्न-भिन्न राजनीतिक विचारों के लोग हो तो सत्याग्रह के तात्कालिक उद्देश्य के बारे में भिन्न-भिन्न प्रकार के राजनीतिक विचारों के वाद-विवाद या उस दृष्टि से की जाने वाली आलोचनाओं को बंद करने में सबको एकमत होना चाहिए।

सत्याग्रही नेताओं का जनता पर इतना काबू होना चैाहिए कि लोग उनकी दी हुई हिदायतों पर खुशी से औ लगन से अमल करें उन की मना की हुई बात या काम कभी न करें। स्वराज अथवा उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्रणाली प्राप्त करने के उद्देश्य से सत्याग्रह करना हो तो सत्याग्रह आरंभ करने के पहले ही महत्व वाले साम्प्रदायिक प्रश्नों के बारे में समझौता हो जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति न रहने देनी चाहिए कि ऐसे सवाल खड़े करके विरोधी पक्ष जनता में फूट डाल सके। सत्याग्रही को की योग्यता वाले प्रकरण में बताई हुई शर्तों में विश्वास होते हुए जो उनका पालन नहीं कर सकते उन्हें सत्याग्रह के तीव्र अर्थात जोखिम वाले कार्यक्रम में शरीक में न होना चाहिए। पर बाहर रहकर वे जनता के विधायक कार्यक्रम को भली-भांति चलाते रहें और उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें । आम जनता को उन्हें पूरा-पूरा सहयोग देना चाहिए।

क्रमशः

88.59 लाख बच्चों को खिलाई जाएगी कृमिनाशक दवा

स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों को एल्बेन्डाजॉल की दवा खिलाकर किया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ

रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में बच्चों को एल्बेन्डाजॉल की दवा खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ किया। उन्होंने बच्चों को अपनी गोद में लेकर स्वयं कृमिनाशक दवा का सेवन कराया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अंतर्गत प्रदेश के 30 जिलों में एक वर्ष से 19 वर्ष तक के 88 लाख 59 हजार बच्चों और किशोरों को एल्बेन्डाजॉल की दवा खिलाई जाएगी। आज दवा खाने से छूट गए बच्चों को 15 फरवरी को मॉप-अप राउंड के दौरान दवा का सेवन कराया जाएगा। शुभारंभ कार्यक्रम में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भी ऑनलाइन मौजूद थे।

स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में भारत की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग पेट में कृमि से प्रभावित हैं। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को रोकता है। कृमि कुपोषण और एनीमिया का खतरा भी पैदा करता है। बच्चों और किशोरों को कृमि के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए हर वर्ष दो बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन कर कृमिनाशक दवा खिलाई जाती है। उन्होंने सभी परिजनों से अपील की कि वे अपने बच्चों को कृमिनाशक दवा अवश्य खिलाएं। उन्होंने इस अभियान में सभी लोगों से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

श्री सिंहदेव ने कहा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर सभी बच्चों और किशोरों को दवा खिलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में 50 हजार 255 शिक्षकों, 47 हजार 094 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 63 हजार 435 मितानिनों को प्रशिक्षित किया गया है। आज आंगनबाडियों, शासकीय स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में कृमि की दवा का सेवन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों के भोजन का बड़ा हिस्सा कृमि खा जाता है। इससे बच्चे कुपोषित और कमजोर होकर एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। बच्चों को सेहतमंद रखने और उनके शारीरिक-मानसिक विकास के लिए पेट की कृमि को खत्म करना जरूरी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोसकर विलास संदिपान ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के शुभारंभ कार्यक्रम में बताया कि इस बार अभियान के दौरान प्रदेश में 88 लाख 59 हजार बच्चों और किशोरों को एल्बेन्डाजॉल की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। रायगढ़ और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में कृमिनाशक दवा के साथ ही राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत फाइलेरिया से बचाव की भी दवा खिलाई जा रही है। रायपुर, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में विगत दिसम्बर माह में एलएफएमडीए अभियान के दौरान कृमि मुक्ति की दवा का सेवन कराया जा चुका है।

शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के उप संचालक डॉ. व्ही.आर. भगत ने कार्यक्रम में बताया कि कृमि मुक्ति के लिए स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों में एल्बेन्डाजॉल 400 एमजी की दवा का सेवन कराया जा रहा है। कृमि मुक्ति के लिए एक वर्ष से दो वर्ष के बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेन्डाजॉल की आधी गोली पीसकर, दो से तीन वर्ष के बच्चों को एक गोली पीसकर, तीन से पांच वर्ष के बच्चों को एक गोली चबाकर तथा छह वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को एक गोली चबाकर पानी के साथ खिलाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कृमिनाशक दवा का सेवन बच्चों व किशोरों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर, एनीमिया की रोकथाम, बौद्धिक विकास तथा शाला में उपस्थिति में सुधार आएगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान अंबिकापुर के नवापारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अत्याधुनिक सोनोग्राफी मशीन का ऑनलाइन लोकार्पण किया। अंबिकापुर के महापौर डॉ. अजय तिर्की और जिला पंचायत के सभापति श्री राकेश गुप्ता सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोकार्पण कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए।

अविश्वास प्रस्ताव में धमतरी जनपद पंचायत अध्यक्ष की हार

धमतरी। धमतरी जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद छोड़ना पड़ा है। अविश्वास प्रस्ताव मे अध्यक्ष गुंजा साहू को जहां मतदान में हार का सामना करना पड़ा, वही मतदान से पहले ही उपाध्यक्ष अवनेंद्र साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जनपद पंचायत में अध्यक्ष गुंजा साहू और उपाध्यक्ष अवनेंद्र साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर शुक्रवार को मतदान हुआ। अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 23 और विपक्ष में महज 2 मत मिले. वहीं अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान होना था, लेकिन उसके पहले ही उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है।

बताया गया कि जनपद में कुल 25 सदस्य शामिल है, जिसमें भाजपा के 13 सदस्य और कांग्रेस के 12 सदस्य हैं. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद भाजपा और कांग्रेस आपसी सहमति बनाने में जुटे हुए हैं. इस बीच 25 में से 20 सदस्यों के अचानक आउट ऑफ रीच जाने से दोनों पार्टियों को सेटलमेंट का मौका नहीं मिल पा रहा है. अविश्वास प्रस्ताव में 25 में से 19 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है। जिसमें से 13 सदस्य भाजपा के तो 12 सदस्य कांग्रेस के हैं।

संक्षिप्त समाचार

विप्र समाज सदैव ही देश व समाज के लिए मार्गदर्शक रहा है - अधिवक्ता अभिनेश अंजय शुक्ला

1रायपुर। कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज रायपुर द्वारा उच्च न्यायालय अधिवक्ता अभिनेश अंजय शुक्ला को भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश पदाधिकारी के रूप में स्थान मिलने पर सम्मान किया गया है। श्री शुक्ला ने कहा की विप्र समाज सदैव ही देश व समाज का कल्याण के लिए ही अपनी क्षमता का उपयोग करते रहा है,अतः ब्राह्मणों की एकता से बदलेगी देश व समाज की तस्वीर। उन्होने यह भी कहा कि अकारण क्रोधित नहीं होते भगवान परशुराम, अधर्म के नाश के लिए उठता है उनका फरसा। विप्र समाज ने हमेशा निस्वार्थ भाव से हर क्षेत्र में काम किया है और नेतृत्व प्रदान किया है। आज उसी समाज के बीच अपने को सम्मानित होता पाकर गौरवान्वित हो रहा हूं और समाज के सदैव खड़ा रहूंगा। उनका आशिर्वचन शिरोधार्य है।

अभा बहुभाषीय नाट्य स्पर्धा-लोकनृत्य उत्सव बस्तर परब कल से

जगदलपुर। श्यामाप्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में अभियान संस्था द्वारा 11 से 14 फरवरी तक आयोजित अखिल भारतीय बहुभाषीय नाट्य स्पर्धा और लोकनृत्य उत्सव बस्तर परब 2023 की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। इसमें देशभर के विभिन्न राज्यों से 11 टीमें भाग ले रहीं हैं, वहीं निर्णायक के रूप में पहली बार एनएसडी दिल्ली से दो सदस्यीय टीम बस्तर पहुंच रही है। इस आयोजन में नाटक सहित लोकनृत्य की भी प्रस्तुति होगी। एनएसडी से आने वाले निर्णायकों में एक ग्वालियर व दूसरे अंबिकापुर और तीसरे जगदलपुर के हिमांशु शेखर झा होंगे। इस दौरान नाट्य परिचर्चा, रंग यात्रा सहित प्रति दिन प्रस्तुतियों के बाद कैन फायर भी लगेगा। शहर में भव्य शोभायात्रा भी निकाली जाएगी। इसमें देशभर से आए कलाकारों द्वारा शहर के मुख्य मार्ग पर अपनी कला का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं शहर में इनका जगह-जगह स्वागत भी किया जाएगा।

अब 11 फरवरी को खुलेगी रेत खदानों की निविदा

बिलासपुर 10 फरवरी 2023/जिले की तीन रेत खदानों के आबंटन के लिए निविदा आमंत्रित किये गये थे। निविदा खोले जाने की तिथि 10 फरवरी निर्धारित की गई थी किन्तु आवश्यक तैयारी निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं हो पाने के कारण अब निविदा 11 फरवरी को सवेरे 10.30 बजे जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में खोली जाएगी। जो भी बोलीदार इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहें, उन्हें रेत निविदा जमा करने के उपरांत प्रारूप 4 में जारी मूल पावती के साथ अपना पहचान पत्र दिखाने पर सभाकक्ष में प्रवेश दिया जायेगा।

पेंशन चयन संबंधी कार्यशाला 16 फरवरी को

बिलासपुर, 10 फरवरी 2023/शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ओ.पी.एस. अथवा एन.पी.एस. के विकल्प चयन में सुविधा हेतु संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 16 फरवरी 2023 को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक सिंचाई विभाग परिसार में स्थित प्रार्थना सभाकक्ष में किया जाएगा।

छग की वेट व पावर लिफ्टिंग टीम वाराणसी के लिए रवाना

रायपुर। 11 से 14 फरवरी को वाराणसी में आयोजित मास्टर्स नेशनल गेम्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ की वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग की टीम शुक्रवार को रवाना हुई। छग वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन मास्टर्स के अध्यक्ष मानिक ताम्रकार ने बताया कि 12 फरवरी को वेट लिफ्टिंग और 13 फरवरी को पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता के लिए चयनित वेट

कल शहर में देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत

बिलासपुर। इस वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन कल 11 फरवरी को किया जाएगा। जिसमें राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, क्लेम संबंधी प्रकरण, पारिवारिक मामले, श्रम कानून से संबंधी मामले, चेक बाउन्स संबंधी मामले, यातायात संबंधी मामले, दूरसंचार, विद्युत संबंधी मामले इत्यादि मामलों का निराकरण किया जाएगा। बिलासपुर के इतिहास में पहली बार जनोपयोगी सेवाओं जैसे बैंक सुविधा, डाकतार सुविधा, बिजली सुविधा, नगर निगम सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित मामलों के लिये राजीनामा के आधार पर त्वरित निराकरण किये जाने के उददेश्य से मोहल्ला लोक अदालत के माध्यम से स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवा बिलासपुर के द्वारा न्याय आपके द्वार को चरितार्थ करते हुए कल 11 फरवरी को मिनी माता बस्ती जरहाभाठा बिलासपुर में विशेष रूप से स्वच्छता प्रणाली के संबंध में देश में प्रथम बार न्यायालय अपने प्रांगण से बाहर आकर मोबाइल वैन में सज्जित कोर्ट रूम के माध्यम से न्याय देने जा रही है। इस संबंध में छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के तत्वधान में उक्त मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। उक्त मोहल्ला लोक अदालत मोबाइल वैन को माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, कार्यपालक अध्यक्ष, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायधीश छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा हरी झंडी दिखाकर सवेरे

विद्या मितान अतिथि शिक्षक कल्याण संघ ने दिया धरना

रायपुर। विद्या मितान अतिथि शिक्षक कल्याण संघ ने कांग्रेस जन घोषणा पत्र में मांगों को बजट में शामिल करने व 2 अंक बोनस के विरोध में शुक्रवार को बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया।

धरना स्थल पर बैठे संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद विद्यामितान शिक्षकों को नियमित करने के बजाए अतिथि शिक्षक नाम दे दिया गया। लगभग 300 विद्यामितान को नौकरी नहीं दिया गया जो आज भी नौकरी से वंचित है। वर्तमान सरकार ने कहा था कि नियमित भर्ती से शिक्षक पदोनति से शिक्षक तथा ट्रांसफर से शिक्षक नहीं आ सकेंगे पर वर्तमान समय में उसका भी पालन नहीं हो पा रहा है। इस सरकार में नौकरशाही चरम सीमा पर है। अतिथि शिक्षकों ने मांग की है कि सरकार अपने वादे अनुरूप नियमितीकरण करें क्योंकि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार गुहार लगा चुके है। आज तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है जिससे वे आक्रोशित हो गए और जन घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने व 2 अंक बोनस के विरोध में उन्होंने आज धरना-प्रदर्शन किया।

सहायक शिक्षक घेरेंगे मुख्यमंत्री निवास

रायपुर। वेतन विसंगति को लेकर सहायक शिक्षक व प्रधान पाठक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और उनके हड़ताल का आज चौथा दिन है। सरकार की ओर से कोई पहल न होता देख अब वे शनिवार को मुख्यमंत्री निवास घेरने जा रहे है। फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष मनीष मिश्रा की अगुवाई में वेतन विसंगति को लेकर चल रहे हड़ताल के बीच पदाधिकारियों की बड़ी बैठक रायपुर कलेक्ट्रेट गार्डन में हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि शनिवार को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। इस दौरान पांच अलग-अलग संभागों से सहायक शिक्षकों व प्रधान पाठक राजधानी रायपुर कूच करेंगे और वेतन विसंगति न्याय पदयात्रा व मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे।

एसईसीएल ने जल आपूर्ति बंद की, माकपा ने दी 24 को चक्का जाम की चेतावनी

कोरबा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बांकी कोयला खदान बंद होने के बाद खनन प्रभावित मड़वाढोढ़ा, पुरैना और बांकी गांव की बस्तियों में पेयजल आपूर्ति बंद किये जाने की कड़ी निंदा की है और पूर्व की तरह पाइप लाइन और बोरवेल के माध्यम से जल आपूर्ति जारी रखने की मांग की है। इस संबंध में कोरबा महाप्रबंधक को दिए गए एक ज्ञापन में माकपा ने 24 फरवरी को कोयला परिवहन रोकने की चेतावनी दी है। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर, माकपा जिला सचिव प्रशांत झा, किसान सभा नेता जवाहर सिंह कंवर, श्रवण कुमार, हीरा सिंह, जगदीश कंवर, लक्ष्मीराम बघेल, सी आर चौहान, अजित कंवर आदि शामिल थे। उल्लेखनीय है कि खनन प्रभावित गांवों में जल आपूर्ति की जिम्मेदारी एसईसीएल की है। जब खनन कार्य चल रहा था, तब एसईसीएल के पानी से बाहरों महीने इन गांवों के तालाब भरे रहते थे और किसान दोहरी फसल

के साथ सब्जी उगा कर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब जल आपूर्ति बंद होने से बढ़ती गर्मी के साथ निस्तारी का संकट बढ़ रहा है और मवेशियों के लिए भी पानी का इंतजाम करना कठिन हो जाएगा।

माकपा नेता झा ने आरोप लगाया कि बांकी खदान से कमाई बंद होते ही अब एसईसीएल अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने से मुकर रहा है, जबकि किसानों की आजीविका सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को पाना ग्रामीणों का अधिकार है। माकपा की मोंगरा वार्ड पार्षद राजकुमारी कंवर ने आरोप लगाया है कि एसईसीएल ग्रामीणों को नगर निगम का पानी खरीदने को मजबूर कर रहा है, जिसका माकपा विरोध करती है।

भरथरी गायन ने मुझे विदेश जाने का अवसर दिया - रेखा

राजिम। राजिम माघी पुन्नी मेला के पांचवे दिन छत्तीसगढ़ की जानी-मानी प्रसिद्ध लोक गायिका रेखादेवी जलक्षत्री ने भरथरी की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के बाद मीडिया सेंटर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपनी आपबीती बताई। उन्होंने कहा कि भरथरी की प्रस्तुति के लिए विदेश जाने की जानकारी अधिकारियों द्वारा मिली। ये सुनकर मुझे डर लगने लगा कि हवाई जहाज में चढ़कर कैसे जाऊंगी? उत्सुकता तो थी, परंतु डर भी लग रही थी। संजय गांधी के प्लेन क्रैश की बात सुनी थी जैसे तैसे जाने का दिन भी आ गया। विभागीय गाड़ी ने एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया गया। मैं साहब से डर के मारे कह रही थी मै नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। इतने पर मुझे तेज आवाज में कहा रेखा चलो प्लने में बैठना है। डर लगेगा तो आंख बंद कर लेना। आज भी हवाई जहाज के पहली यात्रा को याद कर रोमांचित हो जाती हूं।

उन्होंने आगे बताया कि मेरे दादा मेहतर प्रसाद पंडवानी, रामायण, महाभारत इत्यादि प्रस्तुत करते थे, उन्हीं से मुझे यह कला मिली। वह भरथरी गाने के लिए प्रेरित करते थे, वह मेरे गुरू है। मेरे दो भाई कृष्ण और बलराम की अकेली बहन हूं। भाईयों का प्यार मुझे कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। 10 साल की उम्र में पहली बार मंच में प्रस्तुति दी। उसके बाद तो करवां ही चल पड़ा। विदेश यात्रा में पहली बार जर्मनी गई। 13 दिनों तक रहने का सौभाग्य मिला। वहां का कल्चर हमारे देश से बिल्कुल भिन्न था। मास्को फिर जापान गई। अभी तक कुल तीन देश में कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है। मैं अंगूठा छाप हूं, एक भी क्लॉस नहीं पढ़ी हूं, लगातार कार्यक्रमों में आने जाने के कारण हिन्दी भी बोल लेती हूं और अब तो आम बोलचाल की भाषा अंग्रेजी समझ में आ जाती है। श्रीमती जलक्षत्री ने आगे कहा कि राजिम माघी पुन्नी मेला का मंच राष्ट्र को समर्पित है। प्रस्तुति देकर मैं गदगद हो गई हूं। वह कहती है कि प्रदेश सरकार को भरथरी गायन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। राजा भरथरी की जीवन गाथा इसमें उभर कर सामने आती है। इससे आत्मविश्वास बढ़ते है।

क्रीड़ा परिसर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ

बिलासपुर। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज बहतराई स्टेडियम में दो दिवसीय राज्य स्तरीय अंतर क्रीड़ा परिसर खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। राज्य में पहली बार क्रीड़ा परिसरों के बीच खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में 19 क्रीड़ा परिसरों की लगभग 250 खिलाड़ी चार प्रतियोगिताओं में भागीदारी कर रहे है। कार्यक्रम की अध्यक्षता छ.ग. पर्यटन विकास मण्डल के अध्यक्ष श्री अटल श्रीवास्तव ने की।

मुख्य अतिथि की आसंदी से मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि क्रीडा परिसरों की स्पर्धा छ0ग0 शासन द्वारा दूरगामी उद्देश्य को लेकर प्रारंभ की गई है। प्रतियोगिता में 19 क्रीड़ा परिसरों की बालक-बालिकाएं एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शिरकत कर रही है। पेण्ड्रारोड तथा बिलासपुर के खिलाड़ियों के बीच जिम्नास्टिक, हैण्डबॉल एवं तैराकी की स्पर्धा आयोजित की जा रही है। इससे क्रीड़ा परिसर के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय मैदान अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अटल श्रीवास्तव जी ने कहा कि गुरुकुल क्रीड़ा परिसर के छात्रों के जिम्नास्टिक का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय तथा उच्च कोटि का था। उन्होंने दूरस्थ अंचल से आए खिलाड़ी इस मैदान पर खिलाड़ियों को उल्लेखनीय प्रदर्शन करने हेतु शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में स्वागत भाषण जिले के सहायक आयुक्त एवं आयोजन सचिव श्री सी0 एल0 जायसवाल ने दिया। संचालनालय रायपुर से आए अपर संचालक श्री जितेन्द्र गुप्ता ने कहा कि विभाग के क्रीड़ा परिसरों को उन्नत एवं आधुनिक बनाने हेतु माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार प्रयास किए जा रहे है इसी तारतम्य में अंतर क्रीड़ा परिसर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का संचालन श्री सुशील मिश्रा कोच, क्रीडा परिसर बिलासपुर ने किया। पेण्ड्रारोड के छात्रों ने जिम्नास्टिक के करतब का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के प्रथम दिन के परिणाम इस प्रकार रहे। 1500 मीटर की दौड़ में पिछड़ा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर के नैतिक सोनकर ने प्रथम, नारायणपुर के सनौजौरीय ने द्वितीय एवं डोंडी के सुरेश कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

1500 मीटर बालिका की दौड़ में सुखमति जगदलपुर प्रथम, प्रीति कांवरे कांकेर द्वितीय एवं सजना धरमजयगढ़ तृतीय स्थान पर रही। तवाफेंक बालिका में अर्चना तिग्गा धरमजयगढ़ प्रथम, आरूषि पैकरा अंबिकापुर द्वितीय एवं सावित्री टेकाम अंबागढ़ चैकी तृतीय। तवाफेंक बालक वर्ग में रोशन साहू बिलासपुर प्रथम, सोमनाथ नारायणपुर द्वितीय एवं सुनील वाड़फनगर तृतीय स्थान पर रहे।

पशु पालन-बाड़ी विकास से परिवार की समृद्धि में जुटे अंबिका

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

कोरिया। जिले के विकासखण्ड सोनहत में रहने वाले अंबिका प्रसाद अब अकुशल मजदूर से एक किसान बन चुके हैं। पहले काम की तलाश में भटकने वाले अंबिका प्रसाद अपने बाड़ी के विकास में इस कदर जुटे हैं कि अब उन्हे किसी जगह रोजगार की तलाष नहीं है। उनकी पत्नी स्व सहायता समूह से जुड़कर बिहान की मदद का लाभ ले रही हैं और वह पशुपालन के साथ बाड़ी में सब्जी उगाकर अपनी आर्थिक उन्नति की राह बना रहे है।

जनपद पंचायत सोनहत के ग्राम पंचायत ओदारी में रहने वाले 40 वर्षीय अंबिका प्रसाद अपने परिवार के मुखिया हैं। अंबिका प्रसाद बताते है कि लगभग उनके पास चार एकड़ भूमि है पहले इनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं था तो केवल बारिश पर आधारित धान की फसल ले पाते थे। साथ ही भूमि भी उपर नीचे थी तो फसल लेने में भी काफी परेशानी होती थी। फिर तीन वर्ष पूर्व उन्होंने ग्राम पंचायत में आवेदन देकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भूमि समतलीकरण कराने की मांग की। इनके आवेदन के आधार पर 75 हजार रूपए की

स्वीकृति से 2018-19 में मनरेगा योजना से इनके खेतों का सुधार कार्य पूरा हुआ। जब फसल अच्छी हुई तो उन्होंने अपने बचत राशि से एक बोर खनन कराया और सौर सुजला योजना का लाभ लेते हुए बाड़ी विकास का कार्य प्रारंभ किया। साथ ही लगातार मनरेगा के रोजगार मूलक कार्यों में 100 दिन काम करने वाले परिवार के मुखिया के तौर पर चयनित होकर इनके क्षमता विकास के लिए मनरेगा अंतर्गत प्रोजेक्ट उन्नति के तहत जनपद पंचायत स्तर पर निषुल्क बकरीपालन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के बाद अंबिका प्रसाद अपनी पत्नी श्रीमती रजनी बाई के साथ व्यवस्थित तरीके से बकरी पालन के कार्य में जुट गए। अब इनके पास 16 से ज्यादा बकरे बकरियां हैं। साथ ही इनके घर में तीन जोड़े बैल और दो गाय भी है। पशुपालन से इनके घर में पर्याप्त जैविक खाद और दूध की उपलब्धता है। बकरियों को बेचकर प्रतिमाह अंबिका प्रसाद 6 से 8 हजार रूपए कमा रहे है। साथ ही बाड़ी विकास करके हर माह सब्जी उत्पादन कर इनका परिवार 8 से 10 हजार रूपए का लाभ ले रहा है। अभी इनके खेतों में गोभी, मटर, मिर्च आलू सहित कई तरह की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। अंबिका प्रसाद कहते हैं कि हमारे परिवार को अब पैसों की कोई किल्लत नहीं है। उनके दोनों बच्चे अंकितेष और विकास अभी अध्ययन कर रहे है और अंबिका प्रसाद अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत हो गए हैं।

देखी है दरार आज आइने में मैंने...पता नहीं शीशा टूटा था या मैं...

मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार इस वक्त देश में अमृतकाल चल रहा है यह 25 साल चलेगा... देश की आजादी के 100 साल यानि सन 2047 तक चलेगा।देश में 80त्नआबादी के पास खाने के लिए भोजन नहीं हैं(केंद्र सरकार का 5किलो अनाज मुफ्त देने का दावा) करोड़ों लोग कोरोना महामारी में बेरोजगार हो गय हैँ...पिछला बजट अमृतकाल के 25 साल में 60 लाख रोजगार देने की बात की गईं हैं...इस बार बेरोजगारी

का मसला ही गोल है,पर पिछले चुनाव के समय 2करोड़ हर साल रोजगार देने के वादे का क्या हुआ....? इस बजट में उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई करने वालों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब की संख्या भी घटाकर 5 कर दी गई है। किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ...100 स्मार्ट सिटी बनी कि नहीं...साल 2023-24 के बजट में मनरेगा के लिए बजट आवंटन महज 60 हजार करोड़ रुपये का है। यह पिछले साल के मुकाबले 33 फीसदी कम है। इससे उलट एक साल पहले इस योजना के लिए बजट में 73 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। बाद में इसे रिवाइज कर 89,400 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इससे एक साल पहले मतलब 2021-22 में इस योजना को 98,468 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। साल 2020-21 में तो इसके लिए बजट में तो 61,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, पर बाद में इसे रिवाइज कर 1,11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया था।शिक्षा के बजट में कटौती की गईं है। इधर रेल बजट में बड़ी वृद्धि की गईं है पर बुजुर्गो को रियायत नहीं, टिकट रद्द कराने पर जीएसटी में राहत नहीं, मँहगे टिकट में राहत नहीं और यात्री सुविधाओं में कोई राहत नहीं यही उपलब्धि है...?

इस साल के मोदी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट का हाल... खैर हम बजट के इतिहास पर चलते हैं.....ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए हिंदुस्तान में 7 अप्रैल, 1860 को पहला बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था.देश की आजादी के बाद पहले वज़ीरे खज़ाना (वित्त मंत्री) आर. शन्मुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को शाम 5 बजे आज़ाद हिंदुस्तान का पहला बजट पेश किया था. हालांकि यह मुकम्मल बजट नहीं था.आज़ाद हिंदुस्तान का पहला बजट केवल 7 महीने (15 अगस्त, 1947 से 31 मार्च 1948 तक) के लिए ही पेश किया गया था। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का जायज़ा किया गया और कोई नया टैक्स नहीं लाया गया था. देश के इतिहास में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं।देसाई 1959 में भारत के वित्त मंत्री बने थे. उन्होंने 10 बार बजट पेश किया।मोरारजी ने 1964 और 1968 में दो बार अपने जन्मदिन 29 फरवरी को बजट पेश किया।मोरारजी देसाई के बाद पी चिदंबरम ने सर्वाधिक 8 बार बजट पेश किया है। प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिन्हा, वाईबी चौहान और सीडी देशमुख ने 7 बार बजट पेश किया।पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह,यशवंत सिन्हा और अरुण जेटली ही ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने लगातार 5 बार बजट पेश किया. निर्मला सीतारमण ने 4 बार.... ।संसद में बजट पेश करने वाली महिलाओं में सिर्फ इन्दिरा गांधी और निर्मला सीतारमण शामिल हैं।

कभी अनसुईयाजी और डॉ रमन एक दूसरे के खिलाफ थे....?

छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया

उइके और छ्ग सरकार के बीच तल्ख़ी की खबरें आती रहती हैं, आरक्षण मुद्दे पर तो सरकार सीधे-सीधे भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगा चुकी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्यपाल खुद अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। जो बिल विधानसभा से पारित हुआ है उसके बारे में सरकार से पूछने का उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। उसी के आधार पर तो हम कोर्ट गए हैं। कोर्ट ने यदि उसको नोटिस दिया है तो उसका जवाब कोर्ट को देना चाहिए, बाहर नहीं। अगर उनको वकील भी लगाना है तो राज्य सरकार से पूछकर ही लगाएंगी ना... । क्योंकि सरकार की सलाह से ही राज्यपाल काम करती हैं। वैसे सीएम भूपेश बघेल तो 26 जनवरी को महामहिम से मिलने भी गये थे पर उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने दूरी बनाए रखी....? वैसे कभी मप्र कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा रहीं, डॉ चरणदास महंत के साथ मंत्री रहीं अनसुईयाजी से छ्ग का पुराना नाता है, ज़ब खरसिया विधानसभा उप चुनाव हुआ था....वर्ष 1988 में एक बार खरसिया ने मध्यप्रदेश की राजनीतिक फिजां को बदल दिया था, खरसिया संघर्ष के 18 दिनों में ऐसा मंथन हुआ कि उस मंथन से कई हीरे निकले...डॉ.रमन सिंह की तब खरसिया उपचुनाव में ड्यूटी मुड़ीपार गांव में लगी थी,लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के विश्वस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिसमें अपर मुख्य सचिव जैसे लोग खरसिया में डेरा डाले हुए थे,ऐसे में डॉ.रमन सिंह भाजपा की ओर से कमान सम्हाले हुए थे मुड़ीपार में। तब जिस पटेल के घर डॉ.रमन सिंह और उनकी टीम को आश्रय मिला हुआ था,उसने प्रशासनिक दबाब में घर खाली करा दिया गया था । डॉक्टर साहब और उनकी टीम ने बड़ के पेड़ के नीचे डेरा जमाया। गांवों वालों के बीच निशुल्क दवाएं,इंजेक्शन और चेक अप करते हुए उनका विश्वास हासिल करने का प्रयास किया थाअर्जुनसिंह और दिलीप सिंह जूदेव के बीच कठिन मुकाबला हुआ था तब अर्जुनसिंह के प्रचार प्रसार के लिये सुश्री अनसुईयाजी भी आई थीं.....उन्होंने जमकर प्रचार किया था,वे तो काफ़ी बाद में भाजपा की सदस्य बनीं? वे जन्मजात तो भाजपाई नहीं रहीं और न ही संघ से जुडी रहीं...? कांग्रेस की विचारधारा को अच्छे से जानने वालीँ सुश्री अनसुईयाजी से कांग्रेस की इतनी तल्ख़ी क्यों...? वैसे अविभाजित मप्र में विधायक रहते हुए उनके छ्ग की रश्मिदेवी सिंह से भी मधुर सम्बन्ध थे क्योंकि दोनों भोपाल में पड़ोसी भी थे।

छ्ग का पहला बजट...'राम' और 'सेवाराम'...?

अविभाजित मप्र में 1985 बैच के आईएएस सेवाराम दंतेवाड़ा में एसडीम, जगदलपुर, रायपुर में एडीशनल कलेक्टर तथा दुर्ग में कलेक्टर भी रहे। हाल ही में उनसे मुलाक़ात रायपुर में हुई, वे बस्तर घूमने आए थे। चंडीगढ़ में रह रहे इस पूर्व अधिकारी ने बताया कि ज़ब छ्ग बना और पहला बजट बनाना था तब यहाँ किसी भी

अधिकारी को बजट बनाने का पूर्व अनुभव नहीं था तब छ्ग के पहले सीएम अजीत जोगी के अनुरोध पर तब के मप्र के सीएम दिग्विजय सिँह ने मुझे भेजा था और हमारी टीम ने छ्ग का पहला बजट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बने 22साल से अधिक हो गए। अब प्रदेश की आकांक्षाएं लेकिन इसकी कहानी शुरू हुई थी।5 हजार 700 करोड़ रुपए की मामूली राशि से 2001 में इतनी राशि का पहला बजट आया था।नवम्बर 2000 में छत्तीसगढ़ की पहली सरकार ने कामकाज संभाला। नया राज्य, बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन राज्य के पास आय के पर्याप्त साधन नहीं थे। सरकार का कामकाज चलाने के लिए पहले वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव ने करीब 1300 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया था। बाद में 2001-02 के लिए आम बजट आया। उसका आकार करीब 5 हजार 700 करोड़ रुपए था।

छ्ग की नौकरशाही में अब पुरानी बोतल, नई शराब...

भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्य सचिव और रेरा के पूर्व चेयरमैन विवेक ढांड को 'छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग' का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीँ राजभवन ने पूर्व आईएएस तथा सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल को रेडक्रास सोसायटी का चेयरमेन बनाया है तो छ्ग सरकार ने रिटायरमेंट के बाद 2003 बैच के प्रमोटी आईएएस निरंजन दास को संविदा नियुक्ति देकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया है। रिटायरमेंट के पहले तक निरंजन दास के पास एक्साइज कमिश्नर का प्रभार था। सरकार ने संविदा में नियुक्त निरंजन दास को आयुक्त आबकारी फिर बना दिया है । राज्य में अब संविदा वाले तीन आईएएस हो गए हैं। डॉ आलोक शुक्ला स्कूल और तकनीकी शिक्षा के प्रमुख सचिव हैं तो डी डी सिंह मुख्यमंत्री के सचिव के साथ सामान्य प्रशासन विभाग और आदिमजाति कल्याण के सचिव हैं।

अडाणी और 3.75%आम लोगों के शेयर......

अदाणी समूह के 1 अरब 14 करोड़ शेयर में से 73 करोड़ (64 प्रतिशत) खुद अदाणी-परिवार के पास हैं। 18 करोड़ (16 प्रतिशत) विदेशी संस्थानों के पास हैं। सिर्फ़ ढाई करोड़ शेयर (सवा दो फ़ीसदी) आम निवेशकों के पास हैं और साढ़े चार करोड़ (पौने चार प्रतिशत) देसी वित्तीय संस्थानों के पास। सरकार को किस के डूबने की चिंता है? 6 प्रतिशत लोगों की या 91 प्रतिशत सेठों की....?

और अब बस....

- छ्ग के 2008 बैच के आईएएस नीरज बँसोड़, गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव बनाए गये हैं।
- महादेव ऐप डायरेक्टर (सट्टा किंग) सौरभ चंद्राकर के विवाह समारोह में शामिल होने कुछ लोगों के दुबई जाने की खबर है।
- कभी कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी में अजीत जोगी, ताम्रध्वज साहू सदस्य रहे हैँ।अब भूपेश बघेल का सी डब्लू सी का मेंबर बनना तय माना जा रहा है।
- सरल, सौम्य छवि वाले डॉ रमनसिंह की आखिर भाजपा आलाकमान उपेक्षा क्यों कर रहा है.?

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

जीत का मंत्र देने बस्तर आ रहे हैं नड्डा - अरुण साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश

नड्डा के बस्तर दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि श्री नड्डा लोकसभा प्रवास अभियान के तहत भाजपा के जुझारू कार्यकर्ताओं को सफलता का मंत्र देने आ रहे हैं। वे बस्तर से चुनावी शंखनाद करेंगे। श्री साव ने बताया कि 11 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर में रहेंगे। जहां वे लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक लेंगे। श्री नड्डा सुबह 9 बजे दिल्ली से विशेष विमान द्वारा रवाना होकर पूर्वान्ह 11 बजे सीधे मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर बस्तर पहुंचेंगे। सर्वप्रथम जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर में माता का दर्शन करेंगे। मां की पूजा अर्चना के पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा भाजपा कार्यालय जगदलपुर पहुंचेंगे और पार्टी की लोकसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे। श्री नड्डा जनसभा को संबोधित करने के बाद मां दंतेश्वरी विमानतल जगदलपुर बस्तर पहुंचेंगे और विशेष विमान से रवाना होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए कमर कसकर तैयार है। हमारे राष्ट्रीय नेता कार्यकर्ताओं को संघर्ष में जीत का मार्ग प्रशस्त करने वाला मार्गदर्शन देने आ रहे हैं।

झीरम मामलें में रमन सिंह नार्को टेस्ट की चुनौती स्वीकार करे- कांग्रेस

रायपुर। कांग्रेस ने जीरम मामलें में रमन सिंह से नार्को टेस्ट की चुनौती को स्वीकार करने को कहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुये जीरम का क्रूर नरसंहार हुआ था जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं की पूरी पीढ़ी की हत्या कर दी गयी थी। प्रदेश की जनता जानना चाहती है। बस्तर के घोर नक्सल क्षेत्रों में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को रमन सिंह ने क्यो हटवाया था? परिवर्तन यात्रा के ठीक एक हप्ता पहले रमन सिंह स्वयं विकास यात्रा लेकर बस्तर गये थे उनकी विकास यात्रा में पूरी सुरक्षा दी गयी थी। नंदकुमार पटेल, विधाचरण शुक्ल, महेन्द्र कर्मा जैसे नेताओं की उपस्थिति वाली कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को पूरी तरह हटा लिया गया था? रमन सिंह बताये उन्होंने किस उद्देश्य से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को हटाया था?प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह एंव उनके मंत्री मंडलीय सहयोगियों का नार्को टेस्ट हो जाये तो इन सवालों का जवाब जनता को मिल जायेगा। 20 मई 2013 को पुलिसविभाग को सूचित किया गया था कि 25 मई 2013 को परिवर्तन यात्रा जगदलपुर से सुकमा जायेगी। परंतु जेड प्लस सुरक्षा वाले नेताओं के होने पर भी पर्याप्त बल क्यों नहीलगाया गया?

अधिकारियों को धमका कर भाजपा अपनी राजनीतिक हताशा प्रकट कर रही है -कांग्रेस

रायपुर। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा अधिकारियों को दी गई धमकी की कड़ी निंदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सत्ता हाथ से जाने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता इतना बौखला गये है कि वे अब शासकीय कर्मचारियों को धमकाने चमकाने की भाषा का प्रयोग करने लगे है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद काम करने की संस्कृति विकसित हुई है। इससे भाजपा को पीड़ा हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के अब तक के कार्यकाल में भाजपा प्रदेश में मुद्दाविहीन हो चुकी है जनाधार खो चुकी है। हताशा और निराशा में डूबी भाजपा के नेताओं को आगामी के विधानसभा के आमचुनाव में बची खुची 14 सीट भी खो जाने का भय सता रहा है। बृजमोहन अग्रवाल को भाजपा की करारी हार अभी से दिख रही है इसलिए बृजमोहन अग्रवाल अपनी आदत के अनुसार अधिकारियों को धमका रहे हैं यह बेहद निंदनीय है । प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने नगरी निकाय चुनाव के दौरान सार्वजनिक मंच से कलेक्टर और एसपी को धमका रहे थे राजेश मूणत एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे थे गाली गलौज कर रहे थे सुनील सोनी एक अधिकारी को गाली दे रहे।

हादसे में मारे गए बच्चों के परिवार को भूपेश तत्काल सहायता राशि दे : रंजना साहू

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विधायक रंजना साहू ने कांकेर जिले के कोरर इलाके में ट्रक से कुचलकर 7 मासूम बच्चों की मौत पर अब तक पीड़ितों के परिवार को पर्याप्त सहायता राशि न दिए जाने को राज्य सरकार की संवेदनहीनता की हद करार देते हुए तत्काल मृतक बच्चों के परिवार तत्काल सहायता राशि दिए जाने की मांग की है।प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रंजना साहू ने कहा कि इस भयानक सड़क हादसे में 4 से 7 साल के छोटे छोटे 7 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कांग्रेस सरकार की लचर व्यवस्था है। सात घरों के चिराग बुझ गए और सरकार ने अब तक कोई मदद नहीं की। मुख्यमंत्री इतने बड़े हादसे के बावजूद जरा सा भी नहीं पिघले। उनकी संवेदनशीलता किसके लिए

रिजर्व है? छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में कोई संवेदनशीलता नहीं है। यह एक बार फिर साबित हो गया है। मुख्यमंत्री केवल यह कह रहे हैं कि उचित मुआवजा दे देंगे। उनके बयान जाहिर कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए उनके मन में कितना स्थान है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रंजना साहू ने कहा कि यह उचित मुआवजा क्या होता है? छत्तीसगढ़ के बच्चों की जान का उचित मुआवजा क्या है?

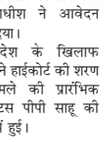

इधर-उधर की बात न कर, ये बता कोल का पैसा गया किधरः सांसद पाण्डेय

रायपुर। सांसद संतोष पांडेय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रति प्रश्न करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने किए वादों को आज तक पूरा नहीं कर पायी है और केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को दी जा रही केन्द्रीय योजनाओं का लाभ भी जनता तक पहुंचने नहीं दे रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से प्रश्न करते हुए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 16 लाख मकान बनाना था परन्तु छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राज्यांश नहीं दिया।जिसके कारण आज गरीब आशा में है कि प्रदेश सरकार उस राज्यांश को जल्द जमा करेगी।कब जमा करने वाले हैं कृपया उसकी भी तिथि बताएं। उन्होंने अपना दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहा कि छत्तीसगढ़िया की बात कह कर के

आप ने राज्यसभा में राजीव शुक्ला, केटीएस तुलसी, रंजीता रंजन को भेजा उन्हें हटा करके बस्तर और सरगुजा के लोगों के प्रतिनिधित्व कर देंगे क्या ? उन्होंने अपना तीसरा प्रश्न करते हुए कहा कि जो कोल का पैसा 540 करोड रुपए तक घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ। जिसमें आइएएस समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत आपके प्यारेलाल और यह रिश्ता क्या कहलाता है सौम्या चैरसिया जेल के अंदर हैं।

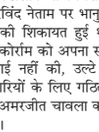

जगदलपुर-कोन्टा मार्ग निर्माण के लिए पर्यावरण की शीघ्र अनुमति के लिए सांसद ने केंद्रीय मंत्री से की मांग

रायपुर। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव को पत्र लिख कर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 (पुराना रा.रा.का. 221) जगदलपुर-सुकमा कोटा मार्ग के उन्नयन एवं चौडीकरण हेतु 8.386 हैक्टेयर वन भूमि के गैर-वानिकी कार्य हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से शीघ्र अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है।

गौरतलब है कि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 23 जून 2022 को एक पत्र राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को लिखा गया था जिसमें उपरोक्त सड़क निर्माण के लिए अनुमति प्रदान करने की मांग की गई थी। सांसद ने अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य को आंध्रा प्रदेश और तेलंगाना राज्य से जोड़ने हेतु ये एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है और राज्य के सर्वागीण विकास के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित इस राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण हेतु जल्द अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

सांसद ने केंद्री वन पर्यावरण मंत्री को अवगत कराया है कि अन्य मार्ग बीजापुर की तरफ से जाने पर लगभग 150 किमी की अतिरिक्त दूरी का भार पड़ता है। बस्तर में उत्पन्न वन औषधि और तेंदूपत्ता के परिवहन का मुख्य मार्ग भी यही है। सड़क की चौड़ाई मात्र 3 मीटर चौड़ी रोड होने के कारण बरसात के कीचड़युक्त दिनो में गाड़ियों के आवागमन के कारण से ट्रैफिक भयंकर रूप से बाधित रहता है और कई कई दिनों तक बंद भी हो

जाता है। क्यूंकि छत्तीसगढ़ राज्य के काफी मरीजो का आंध्रा प्रदेश और तेलंगाना मे इलाज के लिए आना-जाना लगा रहता है और वाहनो का आवागमन बंद रहने के कारण इन मरीजों को आपात स्थिति में बहुत परेशानी होती है। ऐसी ही विकट परिस्थिति का सामना इस क्षेत्र मे रहने वाले आदिवासियों को भी करना पड़ता है।

सांद विजय बघेल ने जनता के हित और प्रदेश के विकास के लिए जगदलपुर, कोन्टा राजमार्ग से तेलंगाना को जोड़ने वाली सड़क के लिए पर्यावरण विभाग की अनुमति जल्द प्रदान करने का अनुरोध किया है।

रायपुर कोर्ट के रीडर की पदोन्नति का मामला,हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

बिलासपुर। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और रायपुर के जिला जज को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के रीडर पितांबर बाघ ने एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई है। इसमें कहा गया है कि कार्य के दौरान उससे एक फाइल खो गई थी। विभागीय जांच के बाद जिला जज ने उसकी दो वेतन वृद्धि रोक दी। इस बीच उसके जूनियर पदोन्नत हो गए। पदोन्नति नहीं मिलने पर उन्होंने विभागीय स्तर पर हाईकोर्ट प्रशासन के समक्ष अपील की, जिसे मजूर कर उसके विरुद्ध दड के आदेश को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने विभाग में अभ्यावेदन दिया और वरिष्ठता तथा 30 साल की सेवा अवधि के आधार पर वेतनमान की मांग की। जिला न्यायाधीश ने आवेदन निरस्त कर दिया।

इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई।

प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला को नोटिस

रायपुर। एआईसीसी ने प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला को नोटिस जारी किया है। उनके साथ-साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम को भी नोटिस थमाया है। नेताम के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया है। अरविंद नेताम पर भानुप्रतापपुर उपचुनाव में पार्टी के खिलाफ खुलकर काम करने की शिकायत हुई थी। नेताम ने सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबरराम कोर्राम को अपना समर्थन दिया था। प्रदेश कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे नेताम और उनकी पत्नी को एआईसीसी अधिवेशन की तैयारियों के लिए गठित समिति में रखा गया। अपुष्ट जानकारी ये है कि इसके लिए अमरजीत चावला को जिम्मेदार ठहराया गया। इस वजह से उन्हें नोटिस दी गई है।

महामहिम से सहमति लेकर ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए

सर्वसम्मति से पारित विधायक 81 दिनों से लंबित क्यों -कांग्रेस

रायपुर।छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश सरकार ने आरक्षण के विषय पर राज्यपाल से सहमति लेकर ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, सर्वसम्मति से विधेयक पारित हुआ, फिर विगत 81 दिन से राजभवन में लंबित क्यों है? संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार विधानसभा में कोई बिल पास हो जाता है तो उसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है, अगर राज्यपाल की असहमति है तो वह बिना हस्ताक्षर किए हैं असहमति जताते हुए राज्य शासन को विधायक लौटा सकती है। विधानसभा उसमें किसी भी तरह के संशोधन या बिना संशोधन के पुनः राज्यपाल को भेजता है तो राज्यपाल को तय समय सीमा के भीतर सहमति देना जरूरी है। बिना विधेयक लौटाए राजनीतिक सवाल जवाब और छत्तीसगढ़ के

97 प्रतिशत स्थानीय आबादी के शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण हितों से संबंधित विधेयक को विगत 81 दिनों से लंबित है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत यह अपेक्षित है कि वह अपने राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कार्य करें, लेकीन अक्सर छत्तीसगढ़ के भाजपाई प्रवक्ता की भूमिका होते हैं।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि इसी तरह का एक बिल विगत 11 नवंबर से झारखंड विधानसभा में पारित होकर राजभवन में आज़ तक लंबित है, लेकिन दिसंबर में ही कर्नाटक विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक पर वहां महामहिम के तत्काल हस्ताक्षर हो गए। संवैधानिक संस्थानों को अपने अधिकार के साथ संवैधानिक कर्तव्यों का भी ध्यान रखना आवश्यक है विश्वसनीयता के लिए संवैधानिक मर्यादा और कार्यकलापों में पारदर्शिता भी अनिवार्य है। विधानसभा में पारित विधेयक पर राज्यपाल सिर्फ सहमति या असहमति व्यक्त कर सकती है बिना किसी ठोस वजह के बिल को इस तरह से लंबे समय तक लंबित रखना संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग नहीं तो क्या है?

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि अनेकों मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के कार्यों की समीक्षा की है। नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष मामले में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के तहत राज्यपाल के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वह स्वयं निष्पादित कर सकता है। 2016 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि राज्यपाल के विवेक के प्रयोग से संबंधित अनुच्छेद 163 सीमित है और उसके द्वारा किए जाने वाली कार्यवाही मनमानी या काल्पनिक नहीं होना चाहिए। विगत दिनों जब महाराष्ट्र में आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया गया और भोर होने से पहले अल्पमत के व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई वह मामला भी सुप्रीम कोर्ट गया और सुनवाई हुई।

आर.एन.आई. रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.